www.railsamacharbureauald.com

सम्पूर्ण भारतीय रेल जगत का प्रथम पाक्षिक, प्रयागराज से प्रकाशित

रेल समाचार ब्यूरो

सन् 1990 से रेल सेवा में समर्पित

"जिस प्रकार रक्त कोशिकाएं शरीर को जीवित रखती हैं, उसी प्रकार भारतीय रेल के डिब्बे इस देश के कोने-कोने तक विकास और एकता का संचार करते हैं।"

"भारतीय रेलवे : वह मौन सेनानी जो विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्र की आपूर्ति श्रृंखला को अटूट बनाए रखती है।"

वर्ष-35 अंक:23-24 रेल समाचार ब्यूरो प्रयागराज 01-31 दिसंबर 2025 (सयुक्तांक), पृष्ठ 12, मूल्यः रु.20 मात्र डाक खर्च (रंगीन सहित)

भारतीय रेलवे ने 11 वर्षों में किया 42,600 से अधिक LHB कोचों का निर्माण

भारतीय रेलवे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' को मजबूत कर रहा है

सूत्र/रे.स.ब्यू- चालू वित्त वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) के दौरान कुल 4,224 से अधिक एलएचबी कोचों का निर्माण किया गया है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में उत्पादित 3,590 कोचों की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाता है। उत्पादन में यह वृद्धि रेलवे इकाइयों में विनिर्माण क्षमता के निरंतर सुदृढ़ीकरण और बेहतर उत्पादन नियोजन को प्रदर्शित करती है।

इस अवधि के दौरान कारखानेवार प्रदर्शन की बात करें तो, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), चेन्नई ने 1,659 एलएचबी कोचों का उत्पादन किया है, इसके बाद मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ), रायबरेली ने 1,234 कोचों का और रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ), कपूरथला ने 1,331 कोचों का उत्पादन किया है। इन सभी ने मिलकर एलएचबी कोच उत्पादन में समग्र वृद्धि में योगदान दिया है।

> भारतीय रेलवे ने लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोचों के उत्पादन में लगातार प्रगति की है, जिन्हें यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा, बेहतर यात्रा आराम और बेहतर परिचालन प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

दीर्घकालिक तुलना की जाए तो हाल के वर्षों में हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति साफ दिखाई देती है। 2014 और 2025 के बीच, भारतीय रेलवे ने 42,600 से अधिक एलएचबी कोचों का उत्पादन किया, जो 2004 और 2014 के बीच निर्मित 2,300 कोचों की तुलना में 18 गुना अधिक है। यह विस्तार एलएचबी कोचों को व्यापक रूप से अपनाकर यात्री परिवहन को आधुनिक बनाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित करता है, जो अपने बेहतर सुरक्षा मानकों और कम रखरखाव की जरुरतों के लिए जाने जाते हैं।

घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर और आयात पर निर्भरता कम करके भारतीय रेलवे, 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल के लक्ष्यों में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। यह संगठन देश की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने और यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने पर केंद्रित है।

"चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है" - श्री अश्विनी वैष्णव

सूत्र/रे.स.ब्यू- रेल, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 28 नवंबर, 2025 को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री को स्टेशन के आधुनिकीकरण परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी। विस्तृत समीक्षा के बाद, श्री अश्विनी वैष्णव ने चंडीगढ़ स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की प्रगति पर खुशी जताई। निरीक्षण के दौरान, रेलवे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे ।

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बात करते हुए, श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड-क्लास स्टेशन के तौर पर पुनर्विकसित किया जा रहा है। कई इनोवेशन किए गए हैं, जिनमें से एक मॉड्यूलर डिजाइन है, जिसमें प्री-फैब्रिकेटेड डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। यह स्टेशन रूफ प्लाजा के जरिए पंचकूला और चंडीगढ़ शहर के दो सिरों को जोड़ेगा। स्टेशन को 462 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया जा रहा है। काम तेजी से चल रहा है। टीम स्टेशन को तेजी से पुनर्विकसित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है।"

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित कर इसका मकसद स्टेशन को विश्व-स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। चंडीगढ़ स्टेशन एक मुख्य गेटवे के तौर पर बहुत अहमियत रखता है, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की प्रसिद्ध जगहों पर जाने वाले ज़्यादातर पर्यटकों और यात्रियों को सेवाएं प्रदान करता है।

तेजी से किए जा रहे इन प्रयासों का फोकस पैसेंजर सुविधाओं को बढ़ाना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और एक मॉडर्न, आसान और कुशल ट्रैवल हब बनाना होगा जो शहर के प्लान किए गए आर्किटेक्चर को दिखाए और इसके उपयोगकर्ताओं की बढ़ती मांगों को पूरा करे।

इससे पहले, केंद्रीय मंत्री ने सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (SCL), मोहाली का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने SCL में रिव्यू मीटिंग की। उन्होंने बताया कि SCL को 4500 करोड़ रुपये के निवेश से आधुनिक बनाकर विस्तार दिया जा रहा है। SCL लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपना रही है।

वाराणसी रेल इंजन निर्यात का बड़ा केंद्र: वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय इंजनों की धमक

अत्याधुनिक तकनीक और निर्माण क्षमता से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा वाराणसी

सूत्र/रे.स.ब्यू- बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (बीएलडब्ल्यू) ने 15 दिसंबर, 2025 को मोजाम्बिक के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित छठे 3300 हॉर्स पावर एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक रेल इंजन का सफल प्रेषण कर रेल इंजन विनिर्माण के क्षेत्र में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि बीएलडब्ल्यू ने मोजाम्बिक के लिए दस 3300 हॉर्स पावर एसी-एसी डीजल-इलेक्ट्रिक रेल इंजन को निर्यात का ऑर्डर हासिल किया है। इन रेल इंजनों की आपूर्ति मेसर्स आरआईटीईईएस के माध्यम से 10 रेल इंजन निर्माण एवं निर्यात संबंधी अनुबंध के तहत की जा रही है। पहले दो रेल इंजन जून 2025 में भेजे गए, इसके बाद तीसरा सितंबर में और चौथा अक्टूबर में भेजा गया। पांचवां रेल इंजन 12 दिसंबर को और छठा 15 दिसंबर को भेजा गया। यह निर्यात वैश्विक मंच पर रेल इंजन निर्माण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है।

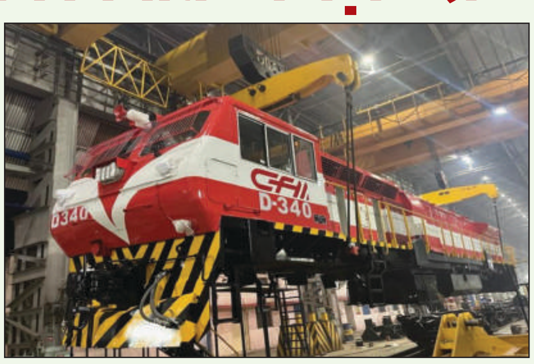

बीएलडब्ल्यू द्वारा निर्मित ये अत्याधुनिक 3300 एचपी केप गेज (1067 मिमी) रेल इंजन 100 किमी प्रति घंटे तक की गति से चलने में सक्षम हैं। इनमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चालक-अनुकूल सुविधाएं जैसे रेफ्रिजरेटर, हॉट प्लेट, मोबाइल होल्डर और आधुनिक कैब डिजाइन मौजूद हैं, जो बेहतर आराम और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करते हैं।

वाराणसी स्थित बीएल- डब्ल्यू भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो रेल इंजन विनिर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। स्वदेशी डिजाइन और उन्नत रेल प्रौद्योगिकी के निर्माण में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए बीएलडब्ल्यू वैश्विक रेलवे बाजारों में भारत की उपस्थिति को सशक्त बना रहा है। बीएलडब्ल्यू ने 2014 से श्रीलंका, म्यांमार और मोजाम्बिक जैसे देशों को रेल इंजन निर्यात किए हैं, जिससे उनकी रेलवे प्रणालियों के विकास में सहायता मिली है।

'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' की परिकल्पना के अनुरूप ये निर्यात भारतीय रेलवे की उस क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, जिसके अंतर्गत वो विश्व में प्रचलित विभिन्न गेज प्रणालियों के लिए रोलिंग स्टॉक का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति कर सकता है। इन पहलों के माध्यम से भारतीय रेलवे भागीदार देशों को उनके रेल अवसंरचना उन्नयन में सहयोग दे रहा है, साथ ही रेलवे रोलिंग स्टॉक और संबंधित सेवाओं के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ कर रहा है। भारत ने अब तक मेट्रो कोच, बोगियां, यात्री कोच, रेल इंजन तथा अन्य महत्वपूर्ण रेलवे उपकरणों का निर्यात यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली आदि यूरोपीय देशों को किया है। अफ्रीका में मोजाम्बिक, गिनी गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका आदि देश शामिल हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख देशों में म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों को भी रेलवे उपकरणों का निर्यात किया गया है।

अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान आईआरसीटीसी वेबसाइट का अपटाइम 99.98% : अश्विनी वैष्णव

भारतीय रेल ने प्रशासनिक और प्रौद्योगिकीय उपायों से सिस्टम सुरक्षा को मजबूत किया है, जिसमें संदिग्ध यूजर आईडी को निष्क्रिय करना भी शामिल है

सूत्र/रे.स.ब्यू- आईआरसीटीसी वेबसाइट का अपटाइम अप्रैल 2025-अक्टूबर 2025 के दौरान 99.98% था, जबकि 2024-25 में यह 99.86% था। भारतीय रेल ने सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए प्रशासनिक और प्रौद्योगिकी दोनों तरह के उपाय किए हैं। प्रशासनिक उपायों में संदिग्ध उपयोगकर्ता आईडी को निष्क्रिय करना, संदिग्ध रूप से बुक किए गए पीएनआर के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना, उपयोगकर्ता आईडी का पुनर्मूल्यांकन आदि शामिल हैं।

सिस्टम सुधार उपायों में जांच और सत्यापन, वास्तविक उपयोगकर्ताओं द्वारा सुचारू बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी सामग्री वितरण नेटवर्क और अत्याधुनिक तकनीक के साथ एंटी बीओटी एप्लिकेशन की भागीदारी शामिल है। इसके अलावा, सिस्टम में सुधार के लिए आईआरसीटीसी के प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के नियमित रूप से तृतीय पक्ष ऑडिट किए जा रहे हैं।

तब से भारतीय रेलवे पर बुक किए गए कुल आरक्षित टिकटों में ई-टिकटिंग की हिस्सेदारी बढ़कर 87% से अधिक हो गई है। हालांकि, विफल लेनदेन/विलंबित रिफंड/बुकिंग त्रुटियों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनके त्वरित समाधान के लिए नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है।

आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) इसके अलावा, आईआरसीटीसी ने एडवांस्ड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) समाधान लागू किए हैं। यह सर्वर का ग्लोबल नेटवर्क है जो यूजर्स तक स्टैटिक कंटेंट ज़्यादा तेजी से और भरोसेमंद तरीके से पहुंचाता है।

भारतीय रेल में क्षमता बढ़ाना और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

भारतीय रेल हर साल औसतन लगभग 58 करोड़ भोजन परोसती है। औसतन लगभग 0.0008% शिकायतें ही मिलती हैं। इन शिकायतों की जांच के आधार पर, पिछले चार वर्षों में 2.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय रेल की लगातार कोशिश रहती है कि सफर करने वाले यात्री को अच्छी गुणवत्ता और हाइजीनिक खाना मिले। इसलिए भारतीय रेल समय-समय पर यात्रियों को मिलने वाले भोजन और सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाता है। यात्रियों का फीडबैक लेने के लिए, पिछले कुछ वर्षों में रेलमदद पोर्टल शुरू करके भारतीय रेल की शिकायत प्रबंधन प्रणाली को मजबूत, सुगम और ज़्यादा आसान बनाया गया है। रेलमदद पोर्टल शुरू होने के साथ, भारतीय रेल ने पैसेंजर को कंप्लेंट और सुझाव दर्ज करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम दिया।

अगर ट्रेन में खाने की क्वालिटी से जुड़ी कोई भी पैसेंजर कंप्लेंट रिपोर्ट की जाती है, तो सर्विस में कमी के लिए सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ तुरंत और सही सजा वाली कार्रवाई की जाती है।

केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी लोकसभा में लिखित जवाब में दी।

गुणवत्ता, हाइजीन और खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ये उपाय किए गए हैं:

- विशेष बेस किचन से भोजन की आपूर्ति।
- पहचानी गई जगहों पर मॉडर्न बेस किचन शुरू करना।
- खाना बनाने की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए बेस किचन में CCTV कैमरे लगाना।
- खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल, आटा, चावल, दालें, मसाला आइटम, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह जैसे पॉपुलर और ब्रांडेड मटीरियल को शॉर्टलिस्ट करना और उनका इस्तेमाल करना।
- बेस किचन में फूड सेफ्टी और साफ-सफाई के तरीकों पर नजर रखने के लिए फूड सेफ्टी सुपरवाइजर तैनात करना।
- ट्रेनों में आईआरसीटीसी सुपरवाइजर तैनात करना।
- खाने के पैकेट पर QR कोड लगाना, जिससे किचन का नाम, पैकेजिंग की तारीख वगैरह जैसी जानकारी दिखाई दे।
- बेस किचन और पेंट्री कार में नियमित रूप से पूरी सफाई और समय-समय पर पेस्ट कंट्रोल।
- फूड सेफ्टी नॉर्म्स का पालन पक्का करने के लिए, हर केटरिंग यूनिट के लिए तय खाद्य सुरक्षा अधिकारी से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) सर्टिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है।
- ट्रेनों में खाने की क्वालिटी पक्का करने के लिए इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत रेगुलर फूड सैंपलिंग।
- पेंट्री कार और बेस किचन में खाने की साफ-सफाई और क्वालिटी की जांच के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाता है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन सर्वे भी किया जाता है।
- फूड सेफ्टी ऑफिसर समेत रेलवे/आईआरसीटीसी अधिकारियों द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण।
- आईआरसीटीसी कैटरिंग स्टाफ की स्किल्स को बढ़ाने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग देता है, जिसमें कस्टमर सर्विस एरिया जैसे कम्युनिकेशन, अच्छा व्यवहार, सर्विस स्टैंडर्ड, पर्सनल ग्रूमिंग और हाइजीन पर ध्यान दिया जाता है।

गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल का माल ढुलाई राजस्व पिछले तीन वर्षों में चार गुना वृद्धि दर्ज करते हुए 2024-25 में 12,608.05 करोड़ रुपये तक पहुंचा

192 मिलियन टन प्रति वर्ष यातायात क्षमता वाले 118 जीसीटी चालू, इससे रसद लागत में कमी आई और रेल कार्गो में वृद्धि हुई

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021 में गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति की शुरुआत के बाद से कुल 306 जीसीटी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। गैर-रेलवे भूमि के साथ-साथ रेलवे भूमि (आंशिक या पूर्ण) पर कार्गो टर्मिनलों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई इस नीति के तहत अब तक 118 नए जीसीटी चालू किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित यातायात क्षमता 192 मिलियन टन प्रति वर्ष (मिलियन टन प्रतिवर्ष) है। इस नीति के लागू होने के बाद से क्षेत्र में लगभग 8,600 करोड़ रुपये का निजी निवेश आकर्षित किया गया है, जो लॉजिस्टिक अवसंरचना में तेजी से हो रहे विस्तार और निजी भागीदारी की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। जीसीटी रेलवे में अधिक माल लाते हैं। इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होने से अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलती है।

महाराष्ट्र राज्य में अब तक एमएमआर क्षेत्र सहित कुल 9 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) चालू किए जा चुके हैं, जिन पर कुल 548.69 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसके अलावा, रेलवे द्वारा अधिक कार्गो का मतलब कम उत्सर्जन है। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य में एमएमआर क्षेत्र सहित माल और पार्सल टर्मिनलों के विकास के लिए 932.34 करोड़ रुपये के 91 कार्यों को मंजूरी दी गई है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जीसीटी पर संचालित यातायात से प्राप्त माल राजस्व का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है -

वित्त वर्ष माल	ढुलाई राजस्व
2022-23	2,901.86 करोड़
2023-24	7,712.36 करोड़
2024-25	12,608.05 करोड़

सुश्री अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में सदस्य (वित्त) का पदभार ग्रहण किया

सूत्र/रे.स.ब्यू-1987 बैच की भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) अधिकारी सुश्री अपर्णा गर्ग ने 01 दिसम्बर, 2025 को रेलवे बोर्ड में सदस्य (वित्त) के रूप में कार्यभार संभाला। वे भारत सरकार के वरिष्ठतम सिविल सेवकों में से एक हैं, जिनके पास 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

सुश्री गर्ग ने कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जिनमें मैसूर में मंडल रेल प्रबंधक, रेल व्हील फैक्ट्री में प्रधान वित्तीय सलाहकार तथा आईआरआईएफएम में महानिदेशक शामिल हैं।

वे शेवनिंग फेलो हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, ब्रिटेन से परिवहन अर्थशास्त्र में एडवांस्ड मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने बोकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, मिलानय आईएनएसईएडी, सिंगापुरय और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद से एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है

भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर 141 मार्ग किलोमीटर में हाथियों से टकराव को रोकने के लिए सक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा घुसपैठ पहचान प्रणाली तैनात की

सूत्र/रे.स.ब्यू-रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाले टकराव को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस उपलब्धि की जानकारी साझा की।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पूर्वानुमानित रखरखाव अनुप्रयोगों में से कुछ इस प्रकार हैं:

- भारतीय रेलवे के कुछ स्टेशनों पर सिग्नलिंग प्रणाली के कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित पूर्वानुमानित रखरखाव से संबंधित पायलट पहल की जा रही है ताकि इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। मापनीय परिणामों में मानक विफलता और पूर्वानुमान तर्क और अलर्ट तंत्र शामिल हैं, जिन्हें इन स्टेशनों पर परीक्षण परिणामों से प्राप्त किया जाएगा।
- रेलवे पटरियों पर हाथियों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए वितरित ध्वनिक प्रणाली (डीएएस) का उपयोग करते हुए सक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता घुसपैठ पहचान प्रणाली (आईडीएस) को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के 141 मार्ग किलोमीटर खंड में लागू किया गया है और भारतीय रेलवे के 981 मार्ग किलोमीटर खंड के लिए निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं। यह प्रणाली लोको पायलटों, स्टेशन मास्टरों और नियंत्रण कक्षों को रेलवे पटरियों के आसपास हाथियों की आवाजाही के बारे में अलर्ट भेजने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि समय पर निवारक कार्रवाई की जा सके।
- भारतीय रेल ने रोलिंग स्टॉक के पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए रोलिंग स्टॉक सिस्टम (ओएमआरएस) की ऑनलाइन निगरानी, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर (वाइल्ड) जैसी उन्नत/सुधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाया है।
- जुलाई 2025 में वेसाइड मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली (एमवीआईएस) को शामिल करने के लिए भारतीय रेल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह चलती ट्रेनों में लटके हुए पुर्जों या गायब घटकों का पता लगाने के लिए एक एआई/एमएल संचालित प्रणाली है।
- भारतीय रेल और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच स्वचालित व्हील प्रोफाइल मापन प्रणाली यह प्रणाली को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह प्रणाली ट्रेन के पहियों की प्रोफाइल का स्वचालित, गैर-संपर्क मापन करने में सक्षम है, जिससे पहियों की ज्यामिति और घिसाव का तत्क्षण मापन सुनिश्चित होता है।

उपलब्धता के अनुसार, भले ही विकल्प न दिया गया हो, वरिष्ठ नागरिकों तथा 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को स्वतः रूप से निचली बर्थ आवंटित की जाएगी

वरिष्ठ नागरिकों, 45+ महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर में 6-7 निचली बर्थ, 3एसी में 4-5 और 2एसी में 3-4 बर्थ

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली कुछ सुविधाएं इस प्रकार हैं:

- वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को निचली बर्थ का आवंटन स्वतः रूप से किया जाएगा, भले ही कोई विकल्प न दिया गया हो, उपलब्धता के अधीन।
- वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर श्रेणी में प्रत्येक कोच में छह से सात निचली बर्थ, वातानुकूलित 3 टियर (3एसी) में प्रत्येक कोच में चार से पांच निचली बर्थ और वातानुकूलित 2 टियर (2एसी) श्रेणियों में प्रत्येक कोच में तीन से चार निचली बर्थ (ट्रेन में उस श्रेणी के कोचों की संख्या के आधार पर) का संयुक्त कोटा निर्धारित करना।

राजधानी/शताब्दी प्रकार की ट्रेनों सहित सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजनों और उनके परिचारकों के लिए आरक्षण कोटा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

- स्लीपर क्लास में चार बर्थ (दो निचली और दो मध्य बर्थ सहित)
- 3एसी/3ई में चार बर्थ (दो निचली और दो मध्य बर्थ सहित)
- आरक्षित द्वितीय श्रेणी (2एस)/वातानुकूलित चेयर कार (सीसी) में चार सीटें
- ट्रेन में खाली होने वाली निचली बर्थ को वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों या गर्भवती महिलाओं (जिन्हें मध्य/ऊपरी बर्थ आवंटित किया गया है) को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सुरक्षा और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन और विकसित किए गए विभिन्न प्रकार के कोच उपलब्ध कराए गए हैं। आरक्षित डिब्बों में प्रवेश और निकास द्वार चिह्नित होते हैं। 'प्रवेश' और 'निकास' के ये संकेत बॉडी साइड प्रवेश द्वारों के पास लगाए गए हैं। सामान्य डिब्बों में, किसी भी द्वार से प्रवेश और निकास किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेलवे सभी यात्रियों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य उनकी यात्रा के दौरान आराम और सुविधा को बढ़ाना है, जिसमें शामिल हैं:

- लगभग सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजन के लिए एक अलग कोच की व्यवस्था की गई है। इन डिब्बों में चौड़े प्रवेश द्वार, चौड़ी बर्थ, चौड़े डिब्बे, चौड़े दरवाजों वाला बड़ा शौचालय, व्हीलचेयर पार्किंग क्षेत्र आदि होते हैं। शौचालयों के भीतर सहारे के लिए दीवारों पर अतिरिक्त ग्रैब रेल लगाए गए हैं तथा वॉशबेसिन और दर्पण को उपयुक्त ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, जिससे दिव्यांग यात्रियों को अधिक सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा के लिए एकीकृत ब्रेल साइनेज अर्थात ब्रेल लिपि के साथ अंकित साइनेज भी उपलब्ध कराए गए हैं।
- आधुनिक अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को दिव्यांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। वंदे भारत ट्रेनों के पहले और आखिरी डिब्बों में व्हीलचेयर, ज्यादा जगह वाले दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालय आदि के लिए विशेष प्रावधान हैं। इसके अलावा, वंदे भारत ट्रेनों के इन डिब्बों और अमृत भारत के सामान-सह-दिव्यांगजन डिब्बों में मॉड्यूलर रैंप की व्यवस्था की गई है ताकि कोच के अंदर सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों को आसानी से चढ़ना और उतरना पड़े।

केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड वित्त पोषण के साथ महाराष्ट्र में रेलवे विकास को गति दी

2009-14 से बजट परिव्यय 20 गुना से अधिक बढ़ा, राज्य में नई पटरियों के चालू होने की संख्या तीन गुना बढ़ी, जिससे प्रमुख विस्तार और आधुनिकीकरण पहल को बढ़ावा मिला

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में रेलवे नेटवर्क के विकास और विस्तार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रेल, सूचना एवं प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में हाल के वर्षों में बढ़े हुए बजटीय समर्थन, तेज परियोजना क्रियान्वयन और व्यापक स्टेशन पुनर्विकास पहलों के माध्यम से हुई उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में महाराष्ट्र के रेलवे बुनियादी ढाँचे में निवेश कई गुना बढ़ा है। 2009-14 के दौरान जहाँ वार्षिक व्यय औसतन 1,171 करोड़ रुपए था, वहीं 2025-26 में यह 20 गुना से भी ज़्यादा बढ़कर 23,778 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे राज्य में बड़े पैमाने पर विस्तार और आधुनिकीकरण कार्य संभव हो पा रहे हैं।

वर्ष 2009-14 और 2014-25 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाले नए ट्रैक के चालू होने/बिछाने का विवरण निम्नानुसार हैः

अवधि	नया ट्रैक शुरू किया गया	नए ट्रैकों के शुरू होने का औसत
2009-14	292 किमी	58.4 किमी/वर्ष
2014-25	2,292 किमी	208.36 किमी/वर्ष (3 गुना से अधिक)

01.04.2025 तक, 89,780 करोड़ रुपये की लागत से कुल 5,098 किमी लंबी 38 परियोजनाएं (11 नई लाइनें, 02 गेज परिवर्तन और 25 दोहरीकरण) पूरी तरह/आंशिक रूप से महाराष्ट्र में आती हैं, स्वीकृत हैं।

महाराष्ट्र में पूर्णतः/आंशिक रूप से शुरू की गई कुछ मुख्य परियोजनाएं जो शुरू की गई हैं, वे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपये में)
1	अहिल्यानगर-बीड-परली वैजनाथ नई लाइन (261 किलोमीटर)	4,957
2	बारामती-लोनंद नई लाइन (64 किमी)	1,844
3	वर्धा-नांदेड़ नई लाइन (284 किमी)	3,445
4	इंदौर-मनमाड नई लाइन (360 किमी)	18,529
5	वडसा-गढ़चिरौली नई लाइन (52 किमी)	1,886
6	जालना-जलगांव नई लाइन (174 किलोमीटर)	5,804
7	दौंड-मनमाड दोहरीकरण (236 किमी)	3,037
8	कल्याण-कसारा तीसरी लाइन (68 किमी)	1,433
9	वर्धा-नागपुर तीसरी लाइन (76 किमी)	698
10	वर्धा-बल्लारशाह तीसरी लाइन (132 किमी)	1,385
11	इटारसी-नागपुर तीसरी लाइन (280 किमी)	2,450
12	राजनांदगांव-नागपुर तीसरी लाइन (228 किमी)	3,545
13	वर्धा-नागपुर चौथी लाइन (79 किमी)	1,137
14	जलगांव-मनमाड चौथी लाइन (160 किलोमीटर)	2,574
15	भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 किमी)	3,285

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025_26 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाले कुल 8,603 किलोमीटर लंबाई के 98 सर्वेक्षण (29 नई लाइन, 2 गेज परिवर्तन और 67 दोहरीकरण) स्वींत किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने इस बात पर भी उल्लेख किया कि पटरियों का उन्नयन और नवीनीकरण एक सतत और जारी रहने वाली प्रक्रिया है। पटरियों का नवीनीकरण, उनकी समयावधि, यातायात, स्थिति आदि के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। 2025-26 (नवंबर 2025 तक) के दौरान, महाराष्ट्र राज्य सहित लगभग 5,100 किलोमीटर पटरियों का नवीनीकरण पूरा हो चुका है। 2014-25 (नवंबर 2025 तक) के दौरान, लगभग 52,000 किलोमीटर पटरियों का नवीनीकरण किया जा चुका है।

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से आने वाली रेलवे आधारभूत ढांचा परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिमी रेलवे क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। इन क्षेत्रीय रेलवे में चालू वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) के दौरान बदली गई पटरियों की लंबाई इस प्रकार हैः

क्षेत्र	चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बदली गई पटरियों की लंबाई (नवंबर 2025 तक किमी में)
मध्य रेलवे	271
दक्षिण मध्य रेलवे	505
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	196
पश्चिमी रेलवे	345
दक्षिण पश्चिम रेलवे	155

स्टेशन विकासः

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में मास्टर प्लान तैयार करना और स्टेशनों के सुधार हेतु क्रम से उनका कार्यान्वयन शामिल है। इस योजना में स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान, आवश्यकतानुसार गिट्टी रहित ट्रैक आदि का प्रावधान, चरणबद्ध तरीके से स्टेशनों का चयन और व्यवहार्यता, तथा लंबी अवधि तक स्टेशनों पर सिटी सेंटर का निर्माण भी शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक 1337 स्टेशनों की पहचान विकास के लिए की गई है, जिनमें से 132 स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं।

महाराष्ट्र में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य अच्छी तरह से शुरू हैं। महाराष्ट्र राज्य में पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण इस प्रकार हैः

राज्य	पूर्ण किए गए स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों का नाम
महाराष्ट्र	17	**आमगांव, बारामती, चंदा किला, चिंचपोकली, देवलाली, धुले, केडगांव, लासलगांव, लोनंद जंक्शन, माटुंगा, मुर्तिजापुर जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नांदुरा, इतवारी जंक्शन, परेल, सावदा, शाहद, वडाला रोड**

अन्य स्टेशनों पर भी कार्य सुचारू रूप से किया गया है। इसका विवरण नीचे दिया गया हैः

वाथर स्टेशनः नए पोर्टिको, स्टेशन भवन में सुधार, वाटर बूथ, नया मुख्य प्रवेश द्वार, पार्किंग क्षेत्र, सर्कुलेटिंग एरिया, प्रवेश लॉबी में सुधार, पार्किंग क्षेत्र की कंपाउंड वॉल, प्लेटफार्म नंबर 1 पर प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म की सतह, प्रतीक्षालय में सुधार, साइनेज और स्टेशन की रोशनी का काम पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम शुरू हो चुका है।

नंदगांव स्टेशनः प्रवेश एवं निकास द्वार, प्लेटफार्म की सतह, प्लेटफार्म शेल्टर, स्टेशन भवन का सुधार, बुकिंग कार्यालय, फुट ओवर ब्रिज, चारदीवारी, परिभ्रमण क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, साइनेज और प्रकाश व्यवस्था का कार्य पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम शुरू हो चुका है।

हडपसर स्टेशनः नए स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, 12 मीटर फुट ओवर ब्रिज, भूमिगत टैंक, प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म सतह सुधार, परिभ्रमण क्षेत्र, स्टेशन प्रकाश व्यवस्था, साइनेज, लिफ्ट, एस्केलेटर और भू-दृश्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम शुरू हो चुका है।

वर्ष 2024 और 2025 में 1,20,579 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी, रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में 5.08 लाख नौकरियां प्रदान कीं: रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

रेलवे ने बिना पेपर लीक, बिना किसी कदाचार और परीक्षा की निश्चितता के साथ, 59,678 पदों के लिए प्रथम/एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा संपन्न की

सूत्र/रे.स.ब्यू- रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रेलवे के आकार, स्थानिक वितरण और संचालन की गंभीरता को देखते हुए, रिक्तियों का उत्पन्न होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है। नियमित संचालन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मशीनीकरण और नवीन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराई जाती है। रिक्तियों को मुख्य रूप से रेलवे द्वारा परिचालन और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियाँ करके भरा जाता है।

वर्तमान में वार्षिक कैलेंडर 2024 और 2025 के अनुसार भारतीय रेलवे में 1,20,579 रिक्तियों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान, सहायक लोको पायलट (एएलपी), तकनीशियन, उप-निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर (जेई) / डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस) / रासायनिक और धातुकर्म सहायक (सीएमए), पैरामेडिकल श्रेणियां, गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (स्नातक), गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (स्नातक), मंत्रिस्तरीय और पृथक श्रेणियां और लेवल-1 श्रेणियां जैसे सहायक, ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन के पदों को भरने के लिए 92,116 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) अधिसूचित की गई।

59,678 पदों के लिए प्रथम चरण/एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) पूरी हो चुकी है। इनका विवरण इस प्रकार है-

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
एएलपी के पद के लिए प्रथम चरण सीबीटी (18,799 रिक्तियां)	18,40,347	156	15
तकनीशियन पद के लिए सीबीटी (14,298 रिक्तियां)	26,99,892	139	15
जेई/डीएमएस/सीएमए के पद के लिए प्रथम चरण सीबीटी (7,951 रिक्तियां)	11,01,266	146	15
आरपीएफ-एसआई पद के लिए सीबीटी(452 रिक्तियां)	15,35,635	143	15
आरपीएफ-कांस्टेबल पद के लिए सीबीटी (4208 रिक्तियां)	45,30,288	147	15
पैरामेडिकल श्रेणियों के लिए सीबीटी (1,376 रिक्तियां)	7,08,321	143	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (स्नातक) के लिए प्रथम चरण सीबीटी (8,113 रिक्तियां)	58,41,774	141	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (स्नातक) के लिए प्रथम चरण सीबीटी (3,445 रिक्तियां)	63,27,473	157	15
मंत्रिस्तरीय एवं पृथक श्रेणियों के लिए सीबीटी (1,036 रिक्तियां)	4,46,013	139	15

एएलपी, जेइ/डीएमएस/सीएमए और गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (स्नातक) के पदों के लिए द्वितीय चरण की सीबीटी भी पूरी हो चुकी है।

विवरण निम्नानुसार हैं: -

परीक्षा	उम्मीदवार	शहर	भाषाएं
एएलपी के पद के लिए द्वितीय चरण सीबीटी (18,799 रिक्तियां)	2,66,363	112	15
जेई/डीएमएस/सीएमए के पद के लिए द्वितीय चरण सीबीटी (7,951 रिक्तियां)	1,17,339	118	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (स्नातक) के लिए द्वितीय चरण सीबीटी (8,113 रिक्तियां)	1,21,931	129	15

एएलपी पद के लिए कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी) भी पूरी हो चुकी है। इसका विवरण इस प्रकार हैः-

परीक्षा	उम्मीदवार	शहर	भाषाएं
एएलपी के पद के लिए सीबीएटी(18,799 रिक्तियां)	1,32,044	84	2

लेवल-1 श्रेणियों के लिए 32,438 रिक्तियों के लिए सीबीटी 27.11.2025 से 140 शहरों में 15 भाषाओं में शुरू हुई। कांस्टेबल (आरपीएफ) के 4,208 रिक्तियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) 13.11.2025 से शुरू हुई।

तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, सब-इंस्पेक्टर (आरपीएफ) और सहायक लोको पायलट सहित विभिन्न पदों के लिए 23,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पैनल को अंतिम रूप दे दिया गया है। इनमें से ज़्यादातर पद सुरक्षा श्रेणियों में हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 28,463 रिक्तियों के लिए सात केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) भी जारी की गई हैं:

क्रम संख्या	सीईएन सं.	पद का नाम	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	अधिसूचना का महीना
1	01/2025	सहायक लोको पायलट	9,970	मार्च 2025
2	02/2025	तकनीशियनों	6,238	जून 2025
3	03/2025	पैरा मेडिकल	434	जुलाई 2025
4	04/2025	अनुभाग नियंत्रक	368	अगस्त 2025
5	05/2025	जूनियर इंजीनियर / डिपो सामग्री अधीक्षक	2,585	अक्टूबर 2025
6	06/2025	एनटीपीसी (स्नातक)	5,810	अक्टूबर 2025
7	07/2025	एनटीपीसी (स्नातक)	3,058	अक्टूबर 2025

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षाएँ काफी तकनीकी प्रकृति की होती हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और संसाधनों का उपयोग और जनशक्ति का प्रशिक्षण शामिल होता है। रेलवे ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और सभी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की। पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक या इसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई।

भारतीय रेलवे में वर्ष 2004-2005 से 2013-2014 तथा 2014-2015 से 2024-2025 के दौरान की गई भर्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः-

अवधि	भर्ती
2004-2005 से 2013-2014	4.11 लाख
2014-2015 से 2024-2025	5.08 लाख

इसके अलावा, व्यवस्था में सुधार के तौर पर, रेल मंत्रालय ने समूह 'ग' के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 2024 से वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने की व्यवस्था शुरू की है। वार्षिक कैलेंडर लागू होने से उम्मीदवारों को निम्नलिखित लाभ हो रहे हैं:-

- उम्मीदवारों के लिए अधिक अवसर।
- हर साल पात्र बनने वालों को अवसर।
- परीक्षा की निश्चितता।
- तीव्र भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्तियाँ।

कार्य की अनिवार्यता के कारण, नियमित पदाधिकारियों के पदों पर नियुक्त होने तक अस्थायी व्यवस्था के रूप में संविदात्मक नियुक्ति का सहारा लिया जाता है। ऐसी संविदात्मक नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और समयबद्ध होती है और यह व्यवस्था रेलवे परिचालन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ही की जाती है, जब तक कि मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार नियमित चयन के माध्यम से पदों को नहीं भरा जाता।

अनुबंध के आधार पर नियुक्ति पूरी तरह से संविदात्मक प्रकृति की होती है और ऐसे कर्मियों को रेलवे सेवा में नियमित रोजगार, समाहित करना या निरंतरता का कोई अधिकार नहीं देती। चूँकि संविदात्मक नियुक्ति केवल तत्काल परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, इसलिए भारतीय रेलवे में ऐसे संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

वंदे भारत एक्सप्रेस की बड़ी उपलब्धि: 2019 से अब तक 7.5 करोड़ यात्रियों ने किया सफर

देशभर में 164 सेवाएं संचालित, 274 जिलों को जोड़ते हुए कनेक्टिविटी और पर्यटन को मिल रहा जबरदस्त बढ़ावा

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस ने फरवरी 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से भारत में रेल यात्रा को पूरी तरह से बदल दिया है। आज, 164 विश्वस्तरीय वंदे भारत सेवाएं देश भर के प्रमुख शहरों को जोड़ती हैं। ये सेवाएं तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्राएं प्रदान करती हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की लोकप्रियता इसके यात्रियों की संख्या से स्पष्ट है। 2019 से अब तक 75 लाख से अधिक यात्री इस अत्याधुनिक ट्रेन का अनुभव कर चुके हैं।

मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित, प्रत्येक ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इनमें स्वचालित प्लग वाले दरवाजे, घूमने वाली सीटें और बायो-वैक्यूम शौचालय शामिल हैं। इनमें जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली और पूर्ण सीसीटीवी कवरेज भी है। ये सुविधाएं प्रत्येक यात्री के लिए विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव सुनिश्चित करती हैं।

वंदे भारत एक्सप्रेस, रेल सेवा यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुई है। ये भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्रों को गति और आराम से जोड़ती हैं। ये ट्रेनें देश भर के 274 जिलों में चलती हैं। इस व्यापक नेटवर्क से पूरे देश में यात्रा, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क में सुधार हो रहा है।

दिल्ली- वाराणसी मार्ग राष्ट्रीय राजधानी को भारत के आध्यात्मिक केंद्र से जोड़ता है। यह तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को एक सुविधाजनक और विश्वसनीय यात्रा विकल्प प्रदान करता है। इसी प्रकार, श्रीनगर- श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग देश के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक तक पहुंच को बेहतर बनाता है। इस मार्ग का उद्घाटन 6 जून 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करता है।

वहीं दूसरी ओर, बेंगलुरु- हैदराबाद ट्रेन सेवा कई यात्रियों की पसंदीदा विकल्प बन गई है। आईटी पेशेवरों और व्यावसायिक यात्रियों द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह सेवा भारत के दो प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्रों को जोड़ती है।

वंदे भारत की शुरुआत 2019 में सिर्फ एक ट्रेन सेवा से हुई थी। आज यह 164 ट्रेनों के नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। ये ट्रेनें हर महीने लाखों यात्रियों को ले जाती हैं। ये ट्रेनें व्यावसायिक यात्रियों की उत्पादकता बढ़ाती हैं। ये परिवारों को आरामदायक यात्रा प्रदान करती हैं। ये तीर्थयात्रियों को सम्मानजनक यात्रा का अनुभव कराती हैं। सड़क और हवाई यात्रा की तुलना में ये कार्बन उत्सर्जन को भी कम करती हैं।

इस जबरदस्त प्रतिक्रिया से पूरे भारत में विश्व स्तरीय रेल अवसंरचना की बढ़ती मांग का पता चलता है। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल जैसी उच्च तकनीक वाली ट्रेनें लोकप्रिय हो रही हैं और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। भविष्य में, आने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह लंबी दूरी के यात्रियों के लिए गति, आराम और आधुनिक सुविधाओं का बेहतरीन संयोजन प्रदान करेगी।

छत्तीसगढ़ में रेल अवसंरचना को नई रफ्तार: अंबिकापुर क्षेत्र के लिए कई नई रेल लाइन परियोजनाएँ तेज।

सूत्र/रे.स.ब्यू- अंबिकापुर तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रेल संपर्क को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में रेल परियोजनाओं को अभूतपूर्व गति प्रदान की जा रही है। यह जानकारी लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

मंत्री ने बताया कि यह प्रश्न सांसद श्री चिन्तामणि महाराज द्वारा पूछा गया था। अंबिकापुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल में कई महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। बोरिडांड अंबिकापुर (सुरजपुर) दोहरीकरण परियोजना (80 किमी) पर कार्य आरंभ किया जा चुका है। अंबिकापुर रामानुजगंज बरवाडीह नई रेल लाइन तथा रामानुजगंज गढ़वा रोड सहायक लाइन (262 किमी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इसी प्रकार सरडेगा पत्थलगांव अंबिकापुर नई रेल लाइन (218 किमी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी पूर्ण कर ली गई है।

उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ के लिए रेल बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-14 के दौरान जहाँ औसत वार्षिक आवंटन 311 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 6,925 करोड़ रुपये हो गया हैं जो 22 गुना से अधिक वृद्धि दर्शाता है।

नया रेल लाइनों का कमीशनिंग भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है। वर्ष 2009-14 के दौरान केवल 32 किमी (औसत 6.4 किमी/वर्ष) रेल लाइनें कमीशन की गई थीं, जबकि वर्ष 2014-25 के दौरान 1,189 किमी (औसत 108.1 किमी/वर्ष) रेल लाइनें कमीशन की गईं जो 15 गुना से अधिक वृद्धि है।

01 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में आंशिक या पूर्ण रूप से स्थित कुल 26 रेल परियोजनाएँ (06 नई लाइनें और 20 दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ) 1,931 किमी लंबाई एवं 31,619 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 1,023 किमी लंबाई का कमीशनिंग पूर्ण किया जा चुका है तथा मार्च 2025 तक 16,325 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अंबिकापुर क्षेत्र सहित पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) में कुल 26 सर्वेक्षणों को, कुल 3,901 किमी लंबाई को कवर करते हुए, स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति यातायात पूर्वानुमान, लाभप्रदता, पहली अंतिम मील कनेक्टिविटी, अपूर्ण कड़ियों को जोड़ना, मार्ग विस्तार, राज्य सरकारों एवं जनप्रतिनिधियों की माँगें, रेलवे की परिचालन आवश्यकताएँ तथा सामाजिक आर्थिक महत्व जैसे मानदंडों पर आधारित होती है।

उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पूर्ण होने का समय भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, सांविधिक अनुमतियाँ, स्थानीय स्थलोंति, कानून-व्यवस्था तथा मौसम आधारित कार्य-दिवस जैसे कारकों से प्रभावित होता है।

सरकार ने आश्वस्त किया है कि अंबिकापुर क्षेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है एवं इनके त्वरित कार्यान्वयन हेतु निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।

रेलवे बोर्ड मुख्यालय में गरिमापूर्ण तरीके से मना 'संविधान दिवस'

सूत्र/रे.स.ब्यू- 'संविधान दिवस' के अवसर पर बुधवार को रेल भवन स्थित रेलवे बोर्ड मुख्यालय में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सतीश कुमार ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संविधान की उद्देशिका का पाठ किया।

संविधान के प्रति दोहराया संकल्प

कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11:00 बजे बोर्ड के सम्मेलन कक्ष में किया गया। अध्यक्ष श्री सतीश कुमार की अगुवाई में उपस्थित सभी कार्मिकों ने भारत के संविधान की उद्देशिका (Preamble) का सामूहिक वाचन किया। इस दौरान सभी ने संविधान के मूलभूत आदर्शों का पालन करने और राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया।

डिजिटल भागीदारी पर भी जोर

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, इस भौतिक समारोह के अलावा डिजिटल माध्यमों से भी संविधान दिवस मनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को ''mygov.in'' और ''constitution75.com'' वेबसाइटों के माध्यम से 'संवैधानिक लोकतंत्र' पर आयोजित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही, संविधान की उद्देशिका का ऑनलाइन वाचन कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का भी आह्वान किया गया।

क्यों मनाया जाता है यह दिवस?

गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया था। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हर साल 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' मनाया जाता है। रेलवे बोर्ड का यह आयोजन देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक नैतिकता के प्रति भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव ने किया उत्तर मध्य रेलवे में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण

सूत्र/रे.स.ब्यू- श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव ने उत्तर मध्य रेलवे में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया है। श्री श्रीवास्तव 1993 बैच के आईआरएसई अधिकारी हैं। यह पदभार उन्होंने निवर्तमान वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री हिमांशु बडोनी के रेल विकास निगम लिमिटेड में डेप्यूटेशन पर स्थानांतरित होने के उपरांत ग्रहण किया है।

ज्ञात हो कि वरिष्ठ उप महाप्रबंधक जोनल रेल के सतर्कता विभाग के प्रमुख होते हैं। इससे पहले श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव मुख्य इंजीनियर/पी एण्ड डी थे। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक/वाराणसी, अपर मंडल रेल प्रबंधक/उत्तर रेलवे जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

पाठकों से अनुरोध

विगत वर्षों की भाँति आगामी वर्ष के लिए अपनी रेल समाचार ब्यूरो पत्रिका को सुरक्षित करने के लिए वार्षिक सद्स्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें, जिससे उक्त पत्रिका आपको नियमित भेजी जा सके।

सहयोग राशि:

१. उच्चतम अधिकारी-5000 रु. मात्र
२. उच्च अधिकारी- 3500 रु. मात्र
३. अधीनस्थ अधिकारी-2500 रु. मात्र
४. रेलकर्मी/अन्य सदस्य-1000 रु. मात्र

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

पंजिकृत कार्यालाय

502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।

कैंप कार्यालय- अनिल केन (रिर्पोटर) कार्यालय 8439 आर्य नगर पहाड़गंज दिल्ली-55

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पडरौना व कुशीनगर जिले के स्टेशनों का भी होगा व्यापक विकास।

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेलवे ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ देशभर के रेलवे स्टेशनों के समग्र पुनर्विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर चरणबद्ध तरीके से स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच, स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और यात्री सुविधाओं में व्यापक सुधार किया जा रहा है।

योजना में चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स, लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप, प्लेटफॉर्म सतह व शेल्टर में सुधार, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' के तहत स्थानीय उत्पादों के कियोस्क, पार्किंग व मल्टीमोडल इंटीग्रेशन, दिव्यांगजन सुविधाएं, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक मीटिंग स्पेस और लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान शामिल है। आवश्यकतानुसार गिट्टी रहित पटरियों और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर विकसित करने की भी परिकल्पना की गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अब तक 1337 स्टेशनों को विकास हेतु चिह्नित किया गया है, जिनमें से 157 स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों पर उन्नयन और आधुनिकीकरण के कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। राज्य के 22 स्टेशनों पर योजना के तहत विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि अन्य स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से कार्य चल रहे हैं। स्टेशनों के विकास/उन्नयन/पुनर्विकास के लिए कार्यो को स्वीकृति देते समय उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कप्तानगंज जंक्शन सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों को विकास हेतु चिह्नित किया गया है। इन स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और अवसंरचना के समग्र उन्नयन के लिए कार्य योजनाबद्ध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। कप्तानगंज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और विस्तार, प्लेटफॉर्म सतह में सुधार तथा 3 मीटर पैदल पार पुल का कार्य पूरा कर लिया गया है। नए स्टेशन भवन, स्टेशन भवन के सुधार, प्रतीक्षालय, परिचलन क्षेत्र एवं दिव्यांगजन सुविधाओं के विकास का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कुशीनगर जिले के पडरौना रेलवे स्टेशन पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, विश्राम कक्ष, पेयजल नल,

मूत्रालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था तथा परिचलन क्षेत्र की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाल के वर्षों में प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) ओवरहेड टैंक के कार्य पूरे किए गए हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पडरौना स्टेशन के नए स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म सतह संबंधी कार्य, परिचलन क्षेत्र में सुधार तथा दिव्यांगजन सुविधाओं के विकास का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन कार्यो से पडरौना स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और यात्रा अनुभव में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन/ आधुनिकीकरण के कार्य सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाते हैं। इस योजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार, स्टेशन-वार या राज्य-वार।

उत्तर प्रदेश राज्य पाँच क्षेत्रीय रेलों पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिनके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 4,358 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से अक्टूबर 2025 तक 2,288 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न वैधानिक स्वीकृतियों और ब्राउनफील्ड चुनौतियों के कारण कार्यो की समय-सीमा निर्धारित करना इस चरण में संभव नहीं है।

2,626 सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन स्वच्छ और संवहनीय रेल परिचालन में सहायक

898 मेगावाट सौर ऊर्जा चालू की गईय 70% का उपयोग कर्षण प्रयोजनों के लिए किया गया, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार

सूत्र/रे.स.ब्यू-भारतीय रेलवे ने अपने रेल नेटवर्क में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में बहुत तेजी से प्रगति की है। वर्तमान में, 2,626 रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। यह व्यापक पैमाने पर अपनाया गया कदम ऊर्जा लागत को कम करने में मदद कर रहा है। यह पूरे देश में स्वच्छ और अधिक संवहनीय रेल परिचालन की ओर बदलाव को भी दर्शाता है।

चालू वित्त वर्ष में इस गति में और वृद्धि हुई है। नवंबर तक 318 स्टेशन सौर ऊर्जा से जोड़े जा चुके हैं। इनके जुड़ने से, सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या 2,626 तक पहुँच गई है।

रेलवे ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नवंबर 2025 तक, इसने अपने परिचालन के लिए 898 मेगावाट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह 2014 में परिचालन के लिए केवल 3.68 मेगावाट सौर ऊर्जा के मुकाबले तीव्र वृद्धि दर्शाता है। यह 2014 के स्तर की तुलना में लगभग 244 गुना की वृद्धि है। कुल चालू क्षमता में से 629 मेगावाट का उपयोग कर्षण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यह सीधे तौर पर इलेक्ट्रिकॉट्रेन के परिचालन को बल देता है। बाकी 269 मेगावाट बिजली गैर-कर्षण जरूरतों को पूरा करती है। इनमें स्टेशन की लाइटिंग, वर्कशॉप, सर्विस बिल्डिंग और रेलवे क्वार्टर शामिल हैं। सौर ऊर्जा का यह संतुलित उपयोग पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करता है। इससे रेलवे संचालन की कुल दक्षता में भी सुधार होता है।

स्टेशनों, भवनों और रेलवे भूमि पर सौर पैनल भारतीय रेलवे की बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वे ऐसा स्वच्छ और संवहनीय तरीके से कर रहे हैं। इन प्रयासों से ऊर्जा सुरक्षा में सुधार हो रहा है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के उपाय 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

भारतीय रेल ने उर्वरक लोडिंग में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिससे देश भर के किसानों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हुई है

चालू वित्त वर्ष में अब तक भारतीय रेल ने 17,168 उर्वरक रैक लोड किए हैं, जिससे ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिली है

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेल भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पूरे देश में उर्वरकों की सुचारू और समय पर आवाजाही सुनिश्चित करता है। इस वर्ष 30 नवंबर तक उर्वरक की लोडिंग 17,168 रेक तक पहुंच गई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 15,369 रेक की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि है। यह वृद्धि रेलवे नेटवर्क के कुशल संचालन को दर्शाती है।

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों को बुवाई के लिए समय पर उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेल ने उर्वरक और खाद्यान्न ले जाने वाली ट्रेनों को प्राथमिकता दी है। इससे देश भर के राज्यों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

आवश्यक माल ढुलाई सेवाओं को मजबूत करके रेलवे लाखों किसानों की मदद कर रहा है। यह ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा और समग्र आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा दे रहा है। यह प्रदर्शन भारतीय रेल की राष्ट्र निर्माण के प्रति संकल्प और भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला को समर्थन देने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

भारतीय रेल विश्वसनीय, व्यापक और कुशल परिवहन प्रदान करके पूरे देश में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उर्वरक रैकों की प्राथमिकता के आधार पर आवाजाही करके, रेलवे किसानों को निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने में मदद करता है, जिससे वे बिना किसी देरी के कृषि कार्य कर सकें। समय पर आपूर्ति होने से फसलों की उत्पादकता बढ़ने के साथ-साथ खेती की आय में वृद्धि होती है और खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है। रेल परिवहन कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, राजमार्गों पर भीड़भाड़ कम करता है और एक पर्यावरण के अनुकूल तथा अधिक विश्वसनीय रसद समाधान प्रदान करता है।

राष्ट्रपति ने मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया

गुना स्थित मियाना स्टेशन ने एलईडी लाइटिंग, बीएलडीसी पंखों और स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम के जरिए 9,687 यूनिट बिजली की बचत की

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेल ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने मध्य प्रदेश के गुना स्थित मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, 2025 प्रदान किया। यह पुरस्कार महिला एवं रेलवे स्टेशन की महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय ने ग्रहण किया। स्टेशन को परिवहन श्रेणी (रेलवे स्टेशन) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में मान्यता दी गई है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देता है। मियाना रेलवे स्टेशन को एलईडी लाइटिंग, बीएलडीसी पंखों और 30-70 प्रतिशत स्मार्ट लाइटिंग सर्किट संचालन प्रणालियों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए चुना गया है। इन उपायों से स्टेशन को 9,687 यूनिट बिजली की बचत करने में मदद मिली है, जो ऊर्जा दक्षता और सतत विकास पर रेलवे के मजबूत फोकस को दर्शाता है।

भारतीय रेलवे ऊर्जा बचत, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल संचालन के लिए प्रतिबद्ध है तथा मियाना रेलवे स्टेशन अपने प्रभावी कार्यान्वयन और सतत विकास के एक मॉडल के रूप में उभर रहा है।

भारत की पहली हाइड्रोजन-चलित ट्रेन-सेट का निर्माण पूरा हुआ, जींद में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया पर आधारित हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है

स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हाइड्रोजन ट्रेन-सेट आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक, वर्तमान में यह ब्रॉड गेज पर चलने वाली विश्व की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली (2400 किलोवाट) ट्रेन-सेट

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेलवे ने रेलवे में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार, प्रायोगिक आधार पर अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए एक अत्याधुनिक परियोजना शुरू की है।

हाइड्रोजन ट्रेन-सेट का निर्माण पूरा हो चुका है। इस ट्रेन-सेट में उपयोग के लिए हाइड्रोजन की आपूर्ति हेतु जींद में एक हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। इस संयंत्र में विद्युत अपघटन प्रक्रिया का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा रहा है, जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन का एक प्रमुख तत्व है।

इस परियोजना में शुरूआती चरण से लेकर प्रोटोटाइप निर्माण और भारतीय रेलवे में पहली बार हाइड्रोजन कर्षण प्रौद्योगिकी के विकास तक का डिजाइन शामिल है। चूंकि हाइड्रोजन ट्रेन और इसके बुनियादी ढांचे को प्रायोगिक आधार पर विकसित किया गया है, इसलिए इस स्तर पर हाइड्रोजन-ईंधन वाली ट्रेनों की लागत की तुलना, स्थापित कर्षण प्रणालियों से करना उचित नहीं होगा।

यह परियोजना वैकल्पिक ऊर्जा से चलने वाली रेल यात्राओं में प्रगति के प्रति भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे देश के परिवहन क्षेत्र के लिए एक स्वच्छ और हरित भविष्य मुमकिन हो पाएगा।

यह जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

हाइड्रोजन ट्रेन-सेट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- भारत में डिजाइन और विकसित की गई यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के प्रति भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- वर्तमान में, यह ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी (10 कोच) और सबसे शक्तिशाली (2400 किलोवाट) हाइड्रोजन ट्रेन है।
- इस ट्रेन में 1200 किलोवाट की दो ड्राइविंग पावर कार (डीपीसी) हैं, जिनकी कुल क्षमता 2400 किलोवाट है, साथ ही आठ यात्री कारें भी हैं।
- इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शून्य है, केवल जल वाष्प का उत्सर्जन होता है।
- रेलवे में अगली पीढ़ी की ईंधन प्रौद्योगिकी के विकास में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

संपादकीय — धुंध में दौड़ती रेल: उम्मीदों का सफर

सर्दियों की सुबह जब उत्तर भारत का पूरा परिदृश्य सफेद धुंध की एक मोटी चादर में लिपट जाता है, तब जीवन की गति जैसे थम सी जाती है। पंछी अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं, लेकिन इस गहरी खामोशी के बीच, एक आवाज गूंजती है लोहे की पटरियों पर पूरी ठसक के साथ दौड़ती रेलगाड़ी की। यह रेलगाड़ी केवल लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की धड़कन है। जब सब कुछ धुंधला होता है, तब रेल की एक सीटी अंधेरे और कोहरे को चीरकर यह आश्वासन देती है कि मंजिल अब दूर नहीं है। रेल के भीतर का संसार बाहर की कड़ाके की ठंड और अनिश्चितता से बिल्कुल अलग होता है। वहां उम्मीदें गर्म होती हैं। कोई मजदूर अपनी रोटी की तलाश में किसी अनजान शहर की ओर बढ़ रहा होता है, तो कोई फौजी अपनी छुट्टियों की यादें समेटे सरहद की ओर। किसी डिब्बे में एक छात्र अपनी परीक्षा के सपनों को बुन रहा होता है, तो कहीं कोई मरीज इलाज की उम्मीद लिए बड़े शहर की ओर रुख कर रहा होता है।

कोहरे की मार अक्सर ट्रेन की रफ्तार को धीमा तो कर देती है, लेकिन उसके इरादों को नहीं बदल पाती। रेल का यह निरंतर सफर हमें जीवन का एक महान दर्शन सिखाता है। यह बताती है कि जब परिस्थितियां धुंधली हों और सामने का रास्ता साफ दिखाई न दे, तब भी रुकना समाधान नहीं है। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। धीमी गति से ही सही, लेकिन बढ़ते रहना ही मंजिल तक पहुँचने का एकमात्र तरीका है। रेल यह जिम्मेदारी बखूबी निभाती है कि वह समाज के हर वर्ग को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, उनकी मंजिल के द्वार तक सुरक्षित पहुँचाए।

अंततः, धुंध में दौड़ती यह रेल हमारे देश की जीवंतता का प्रतीक है। यह उस विश्वास का नाम है जो हर मौसम और हर बाधा पर भारी पड़ता है। जब कोहरा छंटता है और सूरज की पहली किरण पटरियों पर पड़ती है, तब तक रेल हजारों लोगों को उनके अपनों से मिला चुकी होती है। यह महज एक यात्रा नहीं, बल्कि कर्तव्य और भरोसे का वह सिलसिला है जो बिना रुके, बिना थके, सबको उनकी मंजिल तक पहुँचाने के अपने वादे को हर रोज निभाता है।

आपकी कलम से

भारतीय रेल के साथ, साल यह भी बीत गया

पटरियों की उस गूँज में, एक नया अध्याय जुड़ गया,
भारतीय रेल के साथ, साल यह भी बीत गया।
कभी खिड़की वाली सीट मिली, कभी गलियारे में रात कटी,
अनगिनत अजनबियों से मिले, पर मंजिल की चाहत न घटी।
कोहरे की चादर ओढ़कर, जब इंजन ने हुंकार भरी,
नींद भरी उन आँखों में, यादों की एक लहर तरी।
चाय की उस गरम चुस्की में, सवेरा नया मुस्कुराया,
स्टेशनों की चहल-पहल ने, हर बार घर सा अहसास दिलाया।
कहीं छूट गए कुछ अपने, कहीं नए रिश्ते बन आए,
गाड़ी की उस लय के साथ, हम मीलों दूर निकल आए।
अमृत काल की नई चमक, स्टेशनों पर अब दिखने लगी,
विकास की उस तेज रफ्तार से, रेल की सूरत बदलने लगी।
बीते दिनों की खट्टी-मीठी, यादें दिल में बसा ली थीं,
अगले सफर की तैयारी में, हमने टिकटें कटा ली थीं।
वही सफर था, वही उमंग, बस एक साल और बीत गया,
भारतीय रेल के संग चलते, जीवन का एक दौर बीत गया।

संदीप चतुर्वेदी, मुंबई सेंट्रल

भारत का रेल विद्युतीकरण अभियान पूर्णता की ओर: शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में बड़ी छलांग

स्वच्छ ईंधन और त्वरित यात्री परिवहन से सुगम होगा सफरय पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को मिलेगी नई मजबूती

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेलवे अपने लगभग पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण को पूरा करने के करीब है और 99 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पहले ही विद्युतीकृत हो चुका है तथा शेष हिस्सों का काम भी शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। हाल के वर्षों में काम की गति असाधारण रही है। वर्ष 2019 से 2025 के बीच, भारतीय रेलवे ने 33,000 किलोमीटर से अधिक मार्ग का विद्युतीकरण किया, जो औसतन प्रतिदिन 15 किलोमीटर से अधिक की गति से हुआ है। इस अवधि के दौरान विद्युतीकृत कुल दूरी लगभग जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है, जो स्वच्छ और कुशल रेल परिवहन के विस्तार में भारत की व्यापकता और गंभीरता को दर्शाता है।

भारत का ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क लगभग पूरी तरह से विद्युतीकृत है, जो 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 99.2 प्रतिशत तक फैला हुआ है।

भारत की उपलब्धि उन देशों की तुलना में भी उल्लेखनीय है जिनके पास लंबे समय से स्थापित रेल प्रणालियाँ हैं। दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त रेल नेटवर्क में से एक का संचालन करते हुए भी, भारत ने अपनी लगभग पूरे ब्रॉड-गेज प्रणाली का विद्युतीकरण कर लिया है।

इस परिवर्तन से डीजल की खपत कम हुई है, कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, परिचालन लागत घटी है और रेलगाड़ी संचालन की दक्षता और गति में सुधार हुआ है। जहाँ कई विकसित अर्थव्यवस्थाएँ लागत या संरचनात्मक सीमाओं के कारण अब भी डीजल पर बहुत अधिक निर्भर हैं, वहीं भारत ने स्पष्ट योजना और निरंतर कार्यान्वयन के साथ आगे कदम बढ़ाया है।

जैसे-जैसे अंतिम चरण पूरे हो रहे हैं, देश दुनिया के सबसे बड़े पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे प्रणाली में से एक का संचालन करने के लिए तैयार है। यह भारतीय रेलवे के शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लक्ष्य का समर्थन करता है और प्रतिदिन लाखों यात्रियों को स्वच्छ, तेज और अधिक विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करता है।

पहली बार रेल के जरिए राज्य में पहुँची कारें
लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार

सूत्र/रे.स.ब्यू-सैरांग रेलवे स्टेशन पर पहली बार सीधे ऑटोमोबाइल रैक आया, जिसमें गुवाहाटी के पास चांगसारी से 119 मारुति कारें थीं। यह ऐतिहासिक कदम आइजोल में गाड़ियों की उपलब्धता बढ़ाएगा, लंबे सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करेगा, और मिजोरम के ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें डीलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और ग्राहक शामिल हैं, उन्हें फायदा पहुंचाएगा, जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपलब्धि इंडियन रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ाने, क्षेत्रीय विकास को सपोर्ट करने और पूरे देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दर्शाती है।

ऑटोमोबाइल अनलोडिंग

बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन मिजोरम के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दुर्गम भूभाग से सावधानीपूर्वक काटकर बनाई गई यह लाइन 51.38 किलोमीटर लंबी है और 45 सुरंगों से होकर गुजरती है। यह रेलवे लाइन क्षेत्र के देश के शेष भाग के साथ रणनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस रेल लाइन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 सितंबर 2025 को किया था। इस अवसर पर उन्होंने आइजोल (सैरांग) और दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) के बीच राजधानी एक्सप्रेस, आइजोल (सैरांग) और गुवाहाटी के बीच मिजोरम एक्सप्रेस और आइजोल (सैरांग) और कोलकाता के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही मिजोरम का भारत के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क में पूर्ण एकीकरण हो गया।

नई रेल सेवाओं को लेकर यात्रियों की प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक रही है। तीनों ट्रेनें पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं, जिनमें सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस 147 प्रतिशत, सैरांग-गुवाहाटी मिजोरम एक्सप्रेस 115 प्रतिशत और सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस 139 प्रतिशत शामिल हैं। यात्रियों के लिए ये ट्रेनें सुविधाजनक, किफायती और समय बचाने वाली हैं। रेल संपर्क से प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों तक यात्रा आसान हो गई है। साथ ही, आसपास के राज्यों में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच भी बेहतर हुई है।

बैराबी-सैरांग लाइन पर माल ढुलाई का काम उद्घाटन के तुरंत बाद शुरू हो गया। 14 सितंबर 2025 को पहली माल ढुलाई में असम से आइजोल तक 21 सीमेंट वैगन ले जाए गए। तब से, इस मार्ग पर सीमेंट, निर्माण सामग्री, वाहन, रेत और पत्थर के टुकड़े जैसी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन किया जा रहा है।

सैरांग से पहली पार्सल खेप भी 19 सितंबर 2025 को बुक की गई थी, जब एंथुरियम के फूलों को पार्सल वैन (सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस) के माध्यम से आनंद विहार टर्मिनल तक पहुंचाया गया था। 17 सितंबर से 12 दिसंबर 2025 के बीच कुल 17 रेक संचालित किए गए। ये विकासक्रम दर्शाते हैं कि यह लाइन एक विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बन रही है, जिससे परिवहन लागत कम हो रही है और मिजोरम के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में समर्थन मिल रहा है।

जनवरी 2025 से अब तक 3.02 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी निष्क्रियय प्रामाणिक टिकट बुकिंग के लिए एंटी-बॉट उपाय लागू

भारतीय रेल ने मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों से टिकट आरक्षण प्रणाली को और भी दुरुस्त किया

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेल ने अपनी टिकट आरक्षण प्रणाली को मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों से और भी दुरुस्त कर दिया है। इस अभियान के तहत जनवरी 2025 से अब तक कुल 3.02 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी को निष्क्रिय किया जा चुका है। प्रामाणिक टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में प्रभावी एंटी-बॉट उपाय लागू किए गए हैं। सुरक्षा के घेरे को और कड़ा करते हुए ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए 322 रेलगाड़ियों में और आरक्षण काउंटरों पर 211 रेलगाड़ियों में आधार-आधारित ओटीपी सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। इन तकनीकी सुधारों का सीधा लाभ आम यात्रियों को मिल रहा है, जिसके परिणाम- स्वरूप 96 लोकप्रिय रेलगाड़ियों में से 95 प्रतिशत गाड़ियों में तत्काल टिकट की उपलब्धता का समय पहले की तुलना में बढ़ गया है।

इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. उपयोगकर्ता खातों का कड़ा पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन किया गया है। जनवरी 2025 से अब तक लगभग 3.02 करोड़ संदिग्ध उपयोगकर्ता आईडी निष्क्रिय कर दी गई हैं।
2. अकामाई जैसे एंटी-बॉट समाधानों को फर्जी उपयोगकर्ताओं को हटाने और वैध यात्रियों के लिए सुचारू बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
3. तत्काल बुकिंग में दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग हेतु आधार आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सत्यापन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। 4 दिसंबर 2025 तक यह सुविधा 322 रेलगाड़ियों में पहले से ही मिल रही है। उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप, उपर्युक्त 322 रेलगाड़ियों में से लगभग 65 प्रतिशत रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट की उपलब्धता का समय बढ़ गया है।
4. आरक्षण काउंटरों पर तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी को भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है और 04.12.2025 तक इसे 211 रेलगाड़ियों में लागू किया गया है।
5. इन और अन्य उपायों के परिणामस्वरूप, 96 लोकप्रिय रेलगाड़ियों में से लगभग 95 प्रतिशत रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट की उपलब्धता का समय बढ़ गया है।
6. संदिग्ध रूप से बुक किए गए पीएनआर के संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायतें दर्ज की गई हैं।
7. साइबर खतरों से सिस्टम की सुरक्षा के लिए नेटवर्क फायरवॉल, घुसपैठ रोकथाम प्रणाली, एप्लिकेशन डिलीवरी कंट्रोलर और वेब एप्लिकेशन फायरवॉल जैसी कई सुरक्षात्मक परतों का उपयोग किया गया है। यह सिस्टम एक समर्पित, एक्सेस-नियंत्रित डेटा सेंटर में लगाया गया है, जो सीसीटीवी निगरानी और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित है। डेटा सेंटर आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) मानकों के अंतर्गत प्रमाणित है।
   साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व्यापक साइबर ख़तरा खुफिया सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें टेक-डाउन सेवाएं, ख़तरा निगरानी, डीप और डार्क वेब निगरानी और डिजिटल जोखिम सुरक्षा शामिल हैं। ये सेवाएं उभरते साइबर ख़तरों के बारे में सक्रिय और कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करती हैं और बेहतर घटना प्रतिक्रिया को संभव बनाती हैं।
8. आरक्षण प्रणाली की नियमित सुरक्षा जांच सीईआरटी-इन सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा एजेंसियां करती हैं। इसके अतिरिक्त, साइबर हमलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए सीईआरटी-इन और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) टिकट प्रणाली से संबंधित इंटरनेट यातायात की निरंतर निगरानी करती है।

इसके अतिरिक्त, रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, मंडल कार्यालय आदि विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधियों/संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के अनुरोध/सुझाव/प्रतिनिधित्व प्राप्त होते रहते हैं। चूंकि ऐसे अनुरोध/सुझाव/प्रतिनिधित्व की प्राप्ति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए इनका कोई केंद्रीत संकलन नहीं रखा जाता है। हालांकि, इनकी समय-समय पर जांच की जाती है और व्यवहार्य एवं उचित पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है, जो एक निरंतर प्रक्रिया है। यह जानकारी रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भारत डिजिटल गवर्नेंस को समर्थन देने के लिए सुरक्षित, स्केलेबल और एआई-युक्त क्लाउड ढांचे का निर्माण कर रहा है

साल 2030 तक भारत में क्लाउड डेटा सेंटर की क्षमता 4 से 5 गुना बढ़ने का अनुमान

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में दी जानकारी में बताया कि भारत डिजिटल शासन, निजी क्षेत्र के सहयोग और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित, स्केलेबल और एआई-युक्त क्लाउड व्यवस्था का निर्माण कर रहा है।

देश के डिजिटल परिवर्तन और एआई-सक्षम अनुप्रयोगों के बढ़ते उपयोग के चलते सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्रों में क्लाउड सेवाओं की मांग बढ़ रही है।

मेघराज

भारत सरकार की क्लाउड जरुरतों को पूरा करने के लिए, डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक राष्ट्रीय क्लाउड व्यवस्था बनाई गई है।

''जीआई क्लाउड'', जिसे मेघराज के नाम से जाना जाता है, ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण के लिए सुरक्षित, स्केलेबल और सशक्त क्लाउड सुविधाएं प्रदान करता है।

''जीआई क्लाउड-मेघराज'' की प्रमुख विशेषताओं में सरलता, स्केलेबिलिटी, प्रति उपयोग भुगतान प्रणाली, स्व-सेवा प्रावधान, अनुप्रयोगों की तीव्र तैनाती और मांग पर आधारित सेवाओं का प्रावधान आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करता है। आज तक, 2,170 मंत्रालयों/विभागों ने अपने क्लाउड- आधारित अनुप्रयोगों को ''मेघराज'' पर होस्ट किया है।

केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों की क्लाउड जरुरतों को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 26 क्लाउड सेवा प्रदाताओं की क्लाउड सेवाओं को सूचीबद्ध किया है।

इन क्लाउड सेवा प्रदाताओं को मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों (आईएसओ 27001, आईएसओ 27017, आईएसओ 27018 और आईएसओ 20000) के संदर्भ में सफल ऑडिट के बाद सूचीबद्ध किया गया है। इन क्लाउड सेवा प्रदाताओं का विवरण https://ambud.meity.gov.in/ पर उपलब्ध है।

सरकारी क्लाउड सेवा प्रदाता के रूप में, एनआईसीएसआई क्लाउड सेवाओं के प्रावधान हेतु खुली निविदा के जरिए निजी कंपनियों को भी शामिल करता है।

राष्ट्रीय डेटा केंद्र सरकारी विभागों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करते हैं और स्थापित प्रथाओं और प्रक्रियाओं से युक्त, एक स्तरीय सुरक्षा ढांचा लागू करते हुए संभावित खतरों से क्लाउड सेवाओं की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं।

डेटा केंद्रों का विकास

सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बढ़ते डिजिटलीकरण और एआई के तेजी से होते उपयोग के साथ-साथ क्लाउड सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के कारण देश में डेटा केंद्रों का विस्तार हो रहा है।

उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, भारत में क्लाउड डेटा सेंटर की क्षमता करीब 1,280 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो मुख्य रूप से बैंकिंग, बिजली और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना जैसे अहम क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है। अनुमानों के मुताबिक, वर्ष 2030 तक इसमें 4-5 गुना वृद्धि होगी।

वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां पहले से ही भारत के एआई और डेटा सेंटर इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण निवेश कर रही हैं। गूगल ने विशाखापत्तनम में 15 अरब अमेरिकी डॉलर के एआई हब की घोषणा की है, जो भारत में उसका अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जबकि अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) महाराष्ट्र में 83 अरब अमेरिकी डॉलर का डेटा सेंटर स्थापित कर रही है।

वंदे भारत ट्रेनों में स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे और इसे धीरे-धीरे सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू भी उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को वंदे भारत ट्रेनों में संबंधित क्षेत्र के स्थानीय व्यंजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। स्थानीय व्यंजन शुरू करने से यात्रियों का अनुभव काफी बेहतर होगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान मिलने वाले भोजन में उस क्षेत्र की संस्कृति और स्वाद की झलक मिलेगी। यह सुविधा भविष्य में धीरे-धीरे सभी ट्रेनों में लागू की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि फर्जी पहचान के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग पर भारतीय रेलवे की कार्रवाई से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने और फर्जी आईडी का पता लगाने के लिए एक सख्त प्रणाली लागू होने के बाद, आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रतिदिन लगभग 5,000 नई यूजर आईडी बनाई जा रही हैं। नवीनतम सुधारों से पहले, यह संख्या प्रतिदिन लगभग एक लाख नई यूजर आईडी तक पहुंच गई थी।

इन प्रयासों से भारतीय रेलवे को 3.03 करोड़ फर्जी खातों को निष्क्रिय करने में मदद मिली है। इसके अलावा, 2.7 करोड़ यूजर आईडी को या तो अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है या उनकी संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर बंद करने के लिए चिह्नित किया गया है।

केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि टिकट प्रणाली में इस स्तर तक सुधार किया जाए जहां सभी यात्री एक वास्तविक और प्रामाणिक यूजर आईडी के माध्यम से आसानी से टिकट बुक कर सकें।

पश्चिम मध्य रेलवे ने सात माह में लगभग 4959 करोड़ रुपये ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित किया - गत वर्ष की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई।

सूत्र/रे.स.ब्यू- महाप्रबंधक द्वारा राजस्व बढ़ाने के निर्देशों और वाणिज्यप्रचालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप पश्चिम मध्य रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक रूपये 4958 करोड़ 70 लाख का कुल प्रारंभिक राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (रूपये 4618 करोड़ 90 लाख) की तुलना में 7.36 प्रतिशत अधिक है। ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू के मद वाइज आय पर नजर डालें तो यात्री यातायात से रूपये 1492 करोड़ 16 लाख, माल यातायात से रूपये 3214 करोड़ 35 लाख, अन्य कोचिंग मद में रूपये 106 करोड़ 76 लाख एवं विविध आय यानि संड्री से रूपये 145 करोड़ 43 लाख का रेलवे राजस्व प्राप्त किया है।

चालू वित्तीय वर्ष के सात माह में मंडल वाइज बात करें तो जबलपुर मंडल ने रूपये 2957 करोड़ 09 लाख, भोपाल मंडल ने 1068 करोड़ 10 लाख एवं कोटा मंडल ने रूपये 933 करोड़ 51 लाख का कुल प्रारंभिक राजस्व अर्जित किया है।

यात्री यातायात के लिए पमरे द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:-

- स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।
- पमरे से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि को विस्तारित कर चलाया जा रहा है।
- यात्री ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने के लिए अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं।
- पश्चिम मध्य रेल में मिलने वाले प्रायोगिक ठहराव की अवधि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जा रहा है।

माल यातायात के लिए पमरे द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:-

- माल गोदामों में राउण्ड दॉक्ल कॉयानि चौबीस घंटे लोडिंग एवं अनलोडिंग सेवाएँ शुरू की गई।
- नए माल गोदामों को विकसित करके उन्नयन कार्य किया जा रहा है। गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल/साइडिंग को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

अन्य कोचिंग एवं विविध आय यानि संड्री रेवेन्यू के लिए पमरे द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:-

- गैर-किराया राजस्व (नॉन फेयर रेवेन्यू) में वृद्धि के लिए नवाचारों और नवीन अवधारणाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- नई अभिनव गैर-किराया राजस्व विचार योजना (निनफ्रीस) नीति के तहत नई-नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

पश्चिम मध्य रेल द्वारा ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है और आगे भी जारी रखेगा।

श्री वी सोमन्ना ने तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई

नई ट्रेन से तीर्थ पर्यटन, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा

सूत्र/रे.स.ब्यू- रेल और जल शक्ति राज्यमंत्री श्री वी सोमन्ना ने तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस का नई दिल्ली स्थित रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखा कर शुभारंभ किया। तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस शुरू किए जाने से कई दूरगामी लाभ होंगे। इससे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेल संपर्क को काफी मजबूती मिलेगी। यह श्रद्धालुओं के लिए आंध्र प्रदेश की दक्षिण तटीय पट्टी से शिरडी के लिए पहली सीधी ट्रेन सेवा है। यह ट्रेन भारत के दो प्रमुख तीर्थ स्थलों, तिरुपति और शिरडी को सीधे जोड़ कर तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी।

इस नई ट्रेन से इसके मार्ग में तीर्थ पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा यह क्षेत्रीय विकास में सहायक होगी। यह यात्रियों को सुरक्षित, आरामदेह और निर्बाध अंतरराज्यीय यात्रा का विकल्प मुहैया कराएगी। इससे तीर्थयात्रियों के समग्र रेल यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। इस साप्ताहिक ट्रेन से तीर्थयात्री निर्बाध यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन को एक तरफ की यात्रा पूरी करने में लगभग 30 घंटों का समय लगेगा।

श्री वी सोमन्ना ने तिरुपति-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस के शुभारंभ को चार राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल सिर्फ परिवहन का माध्यम नहीं है। यह देश की जीवन रेखा के रूप में क्षेत्रों और संस्कृतियों को जोड़ती भी है।

रेल और जल शक्ति राज्यमंत्री ने कहा कि अब तिरुपति और शिरडी सीधी ट्रेन सेवा से जुड़ गए हैं। यह ट्रेन नेल्लोर, गुंटूर, सिकंदराबाद, बीदर और मनमाड़ समेत 31 महत्वपूर्ण स्थानों पर रुकेगी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से तीर्थ पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने के साथ ही इसके मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक और सिकंदराबाद से सीधी कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। अपने मार्ग में यह एक महत्वपूर्ण

शिव मंदिर परली वैजनाथ को भी जोड़ेगी।

श्री वी सोमन्ना ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 2014 से रेल अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का साझा औसत रेल बजट 886 करोड़ रुपए का था। यह 11 गुना बढ़ कर 2025-26 में 9417 करोड़ रुपए का हो गया। राज्य में 93000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम जारी है। आंध्र प्रदेश में 2014 से अब तक 1580 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई और 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा किया गया। राज्य में वर्तमान में 73 अमृत स्टेशन हैं। श्री सोमन्ना ने 800 फ्लाईओवरों और पुलों के निर्माण, 110 लिफ्ट और 40 एस्केलेटर लगाए जाने तथा 16 वंदे भारत (8 जोड़ी) और 6 अमृत भारत (3 जोड़ी) ट्रेन सेवाओं की शुरुआत का भी जिक्र किया।

उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे तिरुपति में तिरुपति अमृत स्टेशन समेत 312 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। प्रमुख जारी परियोजनाओं में तिरुपति-पकाला-कटपड़ी मार्ग पर 105 किलोमीटर का दोहरीकरण 1215 करोड़ रुपए के खर्च से किया जा रहा है। कुल 83 किलोमीटर की गुडूर-रेनिगुंटा तीसरी लाइन पर 875 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नादिकुड़ी-श्रीकालाहस्ती 310 किलोमीटर नई लाइन पर 5900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा, 287 किलोमीटर की विजयवाड़ा-गुडूर तीसरी लाइन पर 6235 करोड़ रुपए और 25 किलोमीटर की येरपेडु-पुडी बाईपास लाइन पर 490 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

आंध्र प्रदेश के सड़क और भवन तथा अवसंरचना और निवेश मंत्री श्री बीसी जनार्दन रेड्डी ने मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में हिस्सा लिया। इसमें उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में तिरुपति के सांसद डॉ मदिला गुरुमूर्ति, विधान परिषद सदस्य श्री बी कल्याण चक्रवर्ती, तिरुपति से विधानसभा सदस्य श्री ए श्रीनिवासुलु तथा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) बोर्ड के सदस्य श्री भानु प्रकाश रेड्डी भी शामिल थे।

भारत 2027 तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में एक साथ मानव मिशन के साथ दुर्लभ वैश्विक उपलब्धि हासिल करेगा: डॉ. जितेंद्र सिंह

सूत्र/रे.स.ब्यू- विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अगले दशक के लिए भारत के महत्वाकांक्षी रोडमैप की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2027 तक भारत बाहरी अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में एक साथ मानव मिशन शुरू करके दुर्लभ वैश्विक उपलब्धि हासिल करेगा। यह देश के एकीकृत और दूरदर्शी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा कि विकसित भारत/2047 की ओर भारत की वैज्ञानिक यात्रा आत्मविश्वास, क्षमता और उद्देश्य की स्पष्टता से आकार ले रही है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी के करीब पहुंच रहा है, दुनिया न केवल यह देखेगी कि भारत ने क्या हासिल किया है, बल्कि उन मूल्यों, प्रणालियों और रास्तों को भी देखेगी जिनके माध्यम से राष्ट्र ने प्रगति की है।

मंत्री ने कहा कि भारत का स्थायी लोकतंत्र, संवैधानिक ताकत और सभ्यता की निरंतरता उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से हैं और भविष्य के विकास की नींव बनाते हैं।

भारत की बढ़ती खोज की सीमाओं की जानकारी देते हुए, मंत्री ने कहा कि देश अब पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में अनुसंधान जैसे पहले से कम खोजे गए क्षेत्रों में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 2026 की शुरुआत में, भारत 500 मीटर की गहराई तक पहुंचने वाले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन को संपन्न करने की योजना बना रहा है, जो डीप ओशन मिशन के तहत महत्वपूर्ण कदम होगा। यह आने वाले वर्षों में और गहरी गोताखोरी का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे अंततः भारत स्वदेशी सबमर्सिबल मत्स्य (MATSYA) का उपयोग करके 6,000 मीटर तक की गहराई का पता लगा सकेगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि 2027 निर्णायक वर्ष होगा, जब भारत से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की उम्मीद है, साथ ही गहरे समुद्र में मानव अन्वेषण मिशन भी चलाया जाएगा, यह उपलब्धि दुनिया भर में केवल कुछ ही देशों ने हासिल की है। उन्होंने इस दोहरे मिशन को भारत की वैज्ञानिक परिपक्वता और एकीकृत तरीके से जटिल, समानांतर अन्वेषण करने की क्षमता का प्रतीक बताया।

एआई के क्षेत्र में भारत की नेतृत्व क्षमता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई आशाय माइक्रोसॉफ्ट करेगा भारत में अपना सबसे बड़ा निवेश

सूत्र/रे.स.ब्यू- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और सीईओ श्री सत्या नडेला के साथ एक उपयोगी चर्चा के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में भारत की नेतृत्व क्षमता को लेकर आशा व्यक्त की है। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वह एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश भारत में करेगा। प्रधानमंत्री ने माइक्रोसॉफ्ट की इस घोषणा का स्वागत किया और कहा कि यह नवाचार और प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।

प्रधानमंत्री ने श्री सत्या नडेला के एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जहां तक एआई का सवाल है, दुनिया भारत के प्रति आशावादी है। उन्होंने श्री नडेला के साथ हुई चर्चा को बहुत उपयोगी बताया और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश भारत में करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि भारत के युवा इस अवसर का उपयोग नवाचार करने और बेहतर दुनिया के लिए एआई की शक्ति का लाभ उठाने में करेंगे।

बड़ौत से दो मेमू ट्रेनों (दिल्ली जंक्शन-शामली-दिल्ली जंक्शन और दिल्ली शाहदरा-शामली-दिल्ली शाहदरा) को हरी झंडी

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दिनांक 24 नवम्बर, 2025 को बड़ौत स्टेशन पर दिल्ली और शामली के बीच दो नई मेमू ट्रेन सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान, पूर्व सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, विधान परिषद के सदस्य मोहित बेनीवाल, विधानसभा के सदस्य कृष्ण पाल मालिक तथा बड़ौत नगर पालिका की चेयरपर्सन बबीता तोमर की उपस्थिति रहीं।

विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए, श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, '' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय रेल यात्रियों की बेहतर सेवा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली और शामली के बीच दो नई मेमू सेवाओं के प्रारंभ होने से इस क्षेत्र के डेली पैसेंजर्स, छात्र, किसान और प्रोफेशनल्स को बेहतर मोबिलिटी का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि शामली स्टेशन को 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत 25 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है शामली- बागपत क्षेत्र की एक लंबे समय से लंबित मांग, दो नई मेमू ट्रेनों के उद्घाटन के साथ पूरी हो रही है। ये ट्रेनें इस क्षेत्र के लोगों के लिए यात्रा को आसान बना देंगी।''

श्री वैष्णव द्वारा दिल्ली-शामली खंड के दोहरीकरण की घोषणा के समय, बड़ौत स्टेशन पर उपस्थित विशाल जनसमूह ने तालियाँ बजाकर इसका स्वागत किया। मंच पर उपस्थित नेताओं ने क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए श्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी व्यक्त किया।

श्री वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 के बाद 5272 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए हैं जो स्विट्जरलैंड के कुल रेल नेटवर्क के बराबर है। उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों का शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। इसके अलावा वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में 1460 फ्लाईओवर तथा रोड अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्टेशनों पर 154 लिफ्ट और 156 एस्केलेटर लगाए गए हैं, 771 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में अभी 34 वंदे भारत एक्सप्रेस और 26 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

समस्त प्रकार के कानूनी मामलों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
दि. इलाहाबाद ब्लॉक वर्क्स प्रा. लि.
329/255 चक. जीरो रोड इलाहाबाद से मुद्रित एवं 502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित। आर.एन. आई नं. 51097-90 पोस्ट ए.डी.-8
मो. 9773946044 / 9793956044 फोन नं. 0532-2418040

महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर ने गोरखपुर-गोंडा रेल खंड तथा गोंडा परिक्षेत्र का किया निरीक्षण।

सूत्र/रे.स.ब्यू- महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर ने 19 नवम्बर, 2025 को प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी श्री मुकेश मेहरोत्रा, प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री नीलमणि, प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री संजय सिंघल, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबन्धक श्री अनूप कुमार सतपथी, महानिरीक्षक-सह-प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेलवे सुरक्षा बल श्री तारिक अहमद, प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर श्री एम.एल. मकवाना, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री नरेश कुमार, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री मनोज कुमार, मंडल रेल प्रबन्धक/लखनऊ श्री गौरव अग्रवाल, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री पंकज कुमार सिंह, सचिव/महाप्रबन्धक श्री आनन्द ऋषि श्रीवास्तव सहित अन्य शाखाधिकारियों एवं मुख्य परियोजना प्रबन्धक/गतिशक्ति श्री राघवेन्द्र कुमार के साथ मगहर-गोंडा रेल खंड का संरक्षा एवं यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे स्टेशन पुनर्विकास कार्यों तथा रेल संरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा की।

निरीक्षण के आरम्भ में मगहर स्टेशन से हुई जहाँ महाप्रबन्धक ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रस्तावित ले-आउट प्लान एवं चल रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया। तत्पश्चात मगहर-खलीलाबाद खंड के इंटरलाक्ड समपार फाटक संख्या-176 सी का संरक्षा निरीक्षण किया तथा वहाँ तैनात गेटमैन से संरक्षा सम्बन्धी प्रश्न पूछकर उनकी जागरूकता की जांच की।

खलीलाबाद स्टेशन पर महाप्रबन्धक ने अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के पुनर्विकास, सर्कुलेटिंग एरिया, दिव्यांगजन अनुकूल प्रसाधन, उच्च गुणवत्ता प्रकाश व्यवस्था, प्रतीक्षालय तथा यार्ड में प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग का निरीक्षण किया। चुरेब-खलीलाबाद खंड पर मेजर ब्रिज संख्या-238 का भी गहन निरीक्षण किया।

बस्ती स्टेशन पर महाप्रबन्धक ने नवनिर्मित स्टेशन भवन, पार्किंग क्षेत्र एवं ऊँचे प्लेटफॉर्मो के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्री सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा से पहले एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएँ, ताकि यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ मिल सकें। साथ ही रेल पथों से अतिक्रमण हटाने तथा ऊँचे प्लेटफॉर्म बनाने पर विशेष बल दिया।

निरीक्षण के क्रम में बभनान-परसा तिवारी के मध्य समपार फाटक संख्या-223 बी का संरक्षा निरीक्षण किया। कर्व संख्या-09 पर मौजूद इंजीनियरिंग गैंग के गैंगमैनों से उनकी समस्याएँ सुनीं तथा उनसे वार्ता कर उनकी दक्षता की जांच की और उत्साहवर्धन किया। स्वामीनारायण छपिया रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित स्टेशन के प्लेटफॉर्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण किया।

महाप्रबन्धक श्री उदय बोरवणकर ने सभी अधिकारियों को संदेश दिया कि रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पूर्वोत्तर रेलवे की प्राथमिकता है तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों का कायाकल्प शीघ्र पूरा कर यात्रियों को आधुनिक एवं सुरक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

निरीक्षण के अगले चरण में गोंडा परिक्षेत्र के अंतर्गत गोंडा लोको शेड के निरीक्षण के दौरान महाप्रबन्धक ने सर्वप्रथम ओवरहालिंग अनुभाग, बोगी अनुभाग, विद्युत रनिंग शेड के इन्फ्रास्ट्रक्चर व उक्त अनुभागों में लोको के रखरखाव तथा शेड्यूल अनुरक्षण कार्य का जायजा लिया। महाप्रबन्धक ने लोको अनुरक्षण के दौरान पालन किए जाने वाले सुरक्षा मानकों तथा मशीनों की तकनीकी बारीकियों पर संबंधित अधिकारियों व पर्यवेक्षकों से जानकारी ली। इसके पश्चात गोंडा लोको शेड में बोगी सेक्शन के नवीन नवनिर्मित शेड का कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारी से फीता कटवा कर उद्घाटन किया। महाप्रबन्धक ने लोको शेड में लोको अनुरक्षण में लगने वाले विभिन्न उपकरणों का अवलोकन किया तथा निरंतर मॉनिटरिंग पर बल दिया।

इसके पश्चात हॉक आई सर्टिफिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने महाप्रबन्धक श्री बोरवणकर को लोको शेड गोंडा द्वारा गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली (क्यू.एम.एस.) के लिए गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक आई.एस.ओ. 9001:2015, पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली के लिए आई.एस.ओ. 14001:2015, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली के लिए आई.एस.ओ. 45001:2018, ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली के लिए आई.एस.ओ. 50001:2018 प्रमाण पत्र प्रदान किया।

इस अवसर पर लोको शेड, गोंडा से अनुरक्षित 200वें लोकोमोटिव को महाप्रबन्धक श्री उदय बोरवणकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इसके पश्चात उन्होंने बी.सी.एन. रूटीन ओवरहालिंग डिपो में अनुरक्षण अनुभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान महाप्रबन्धक श्री बोरवणकर ने उद्यान वाटिका में पौधारोपण भी किया। इसके उपरान्त गोंडा स्टेशन पर संरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया।

भारत ने प्राकृतिक जीवन और गांधीवादी मूल्यों पर जोर के साथ, पुणे के निसर्ग ग्राम में 8वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया

"प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी जीवन शैली है जो इंसानों और प्रकृति के बीच तालमेल बिठाती है": महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत

सूत्र/रे.स.ब्यू- 8वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस (नेचुरोपैथी डे) समारोह का आखिरी कार्यक्रम पुणे के येवालेवाड़ी में निसर्ग ग्राम में हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) के तीन दिन के प्राकृतिक महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें लोगों, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और छात्रों ने भाग लिया।

महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) सिर्फ उपचार की प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो इंसानों और प्रकृति के बीच तालमेल बिठाती है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को यह सोच दी थी, जिसमें स्वस्थ, आत्मनिर्भर और आध्यात्मिक रूप से जुड़े समाज पर जोर दिया गया था, और एनआईएन इसी सोच को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा समग्र स्वास्थ्य का रास्ता देती है और राष्ट्रीय मोटापा कम करने के कैंपेन में अहम भूमिका निभा सकती है।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री प्रतापराव जाधव, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अच्छी सेहत के लिए स्वस्थ जीवनशैली, रसायन मुक्त खुराक और प्रकृति के साथ तालमेल जरूरी है। उन्होंने जोर दिया, "सेहत खरीदी नहीं जा सकती-इसे कमाना पड़ता है।" उन्होंने गांधीजी के कार्यो को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस कार्यक्रम के दौरान एनआईएन की प्रकाशित की गई किताबें रिलीज की गई और संस्थान को समर्पित एक खास यादगार डाक टिकट भी जारी किया गया। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया और दादाजी डॉ. दिनश के. मेहता अवॉर्ड जैसे पुरस्कार दिए गए।

उपस्थित लोगों में आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव डॉ. कविता जैन और एनआईएन के प्रभारी निदेशक अमरेंद्र सिंह शामिल थे। महोत्सव ने प्राकृतिक खुराक, जीवनशैली में अनुशासन और देश के स्वास्थ्य एवं आत्म-निर्भरता के लिए गांधीजी की स्थायी विरासत के संदेश पर जोर दिया।

भारत और जर्मनी ने बर्लिन में वैकल्पिक दवाओं पर तीसरे संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक में पारम्परिक दवाओं पर सहयोग को आगे बढ़ाया

सूत्र/रे.स.ब्यू- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और फेडरल स्वास्थ्य मंत्रालय, जर्मनी के बीच वैकल्पिक दवाओं पर तीसरे संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक 18 से 20 नवंबर 2025 तक बर्लिन में आयोजित हुई। यह बैठक पारम्परिक और एकीकृत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत-जर्मनी सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मोनालिशा दास ने किया, जिसमें सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. (डॉ.) रविनारायण आचार्य और सीसीआरएच के डायरेक्टर जनरल डॉ. सुभाष कौशिक जैसे प्रमुख अधिकारी शामिल थे। जर्मनी के अधिकारियों में पॉल जुबेइल (हेड ऑफ डिवीजन यूरोपियन एंड इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी) और प्रोफेसर डॉ. मेड. जॉर्ज सीफर्ट (हेड ऑफ कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ट्रेडिशनल एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, चौरिटे बर्लिन) शामिल थे।

चर्चा तीन विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित थी: पारंपरिक दवा को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल करना (एकीकरण), मरीजों तक पहुँच के लिए प्रतिपूर्ति के रास्ते बनाना, और विनियामकीय मंजूरी प्रणाली को मजबूत करना। ये विषय प्रमाणों पर आधारित और लोगों पर केंद्रित पारंपरिक दवा के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए:

- चौरिटे यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटेंस सेंटर फॉर ट्रेडिशनल एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साथ मिलकर रिसर्च के मौकों की तलाश करना और आयुष मंत्रालय के साथ प्रस्तावित एमओयू को आगे बढ़ाना।
- कम्युनिटी हॉस्पिटल हैवेलहोहे में इंटीग्रेटिव केयर और रिसर्च के तरीकों की समीक्षा करना।
- फेडरल जॉइंट कमेटी (जी-बीए) के साथ पारंपरिक दवा से जुड़े इंश्योरेंस और प्रतिपूर्ति के तरीकों पर चर्चा करना।

यह मिशन आयुष प्रणाली को वैश्विक बनाने और प्रमाणों पर आधारित एकीकरण के लिए मजबूत फ्रेमवर्क बनाने की आयुष मंत्रालय की रणनीतिक कोशिशों को प्रदर्शित करता है। मंत्रालय ने कहा कि जर्मनी के साथ सहयोग से शोध, विनियामकीय तालमेल और एकीकृत स्वास्थ्य समाधान तक मरीजों की पहुँच में तेजी आएगी।

आयुष मंत्रालय के अधीन आने वाले पीसीआईएमएंडएच ने एएसयूएंडएच औषधि विनियमन और गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच) ने 24 से 28 नवंबर, 2025 तक आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों के नियामक, शैक्षणिक, गुणवत्ता नियंत्रण और विनिर्माण क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों के लिए एक पांच दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य औषधि नियामकों, प्रवर्तन अधिकारियों, गुणवत्ता नियंत्रण कर्मियों, सरकारी विश्लेषकों और शोधकर्ताओं के ज्ञान और कौशल को सुदृढ़ करना है। आयुष मंत्रालय की सलाहकार (होम्योपैथी), डॉ. प्रीता किझाक्कुटिल, ने उद्घाटन सत्र में उन्नत उपकरणों और आधुनिक विश्लेषणात्मक तकनीकों को अपनाने के लिए पीसीआईएमएंडएच की सराहना की। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के निदेशक, प्रो. (डॉ.) काशीनाथ समगंडी, ने पीसीआईएम- एंडएच द्वारा विकसित औषधकोशों की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति पर प्रकाश डाला।

पीसीआईएमएंडएच के निदेशक डॉ. रमन मोहन सिंह ने आयोग के अधिदेश और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के मानक-निर्धारण में इसकी भूमिका का उल्लेख किया।

अगले पांच दिनों में, प्रतिभागियों को विशेषज्ञों के नेतृत्व में व्याख्यान, अनुभव दौरे और व्यावहारिक सत्र प्राप्त होंगे, जिनमें एनएबीएल प्रत्यायन, अच्छे विनिर्माण अभ्यास (जीएमपी), और एएसयूएंडएच दवाओं का फार्माकोग्न स्टिक, माइक्रोबायोल जिकल और औषधीय मूल्यांकन जैसे विषय शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में पीसीआईएमएंडएच प्रयोग-शालाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण और दवा निर्माण इकाइयों जैसे डॉ. विलमर श्वाबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा और हमदर्द लैबोरेटरीज इंडिया, गाजियाबाद का क्षेत्रीय दौरा भी शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों की तकनीकी दक्षता को बढ़ाना है।

देश भर से कुल 35 प्रतिभागी इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, जिनमें राज्य औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक, प्रोफेसर, और राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (चेन्नई), राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (जयपुर) जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। यह कार्यक्रम भारत में एएसयूएंडएच दवाओं के नियामक तंत्र को मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आगे बढ़ाने की देश की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में आयुष मंडप एक प्रमुख आकर्षण

सूत्र/रे.स.ब्यू- आयुष मंत्रालय भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2025 में ''आयुष के साथ - स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत'' थीम के तहत देश की पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा विरासत का प्रदर्शन कर रहा है। आयुष मंडप मेले में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक बनकर उभरा है, जो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी के समग्र स्वास्थ्य समाधानों को जानने के लिए हजारों आगंतुकों को आकर्षित कर रहा है।

मंडप के मुख्य आकर्षण:

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए): इन्होंने आयुर्वेद-आधारित पोषण पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें रागी नाचोस, सुंथ्यादि लड्डू, और यवदी सत्तू जैसे शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए कार्यात्मक खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए। विशेषज्ञों ने एनीमिया प्रबंधन और पाचन स्वास्थ्य में उनके लाभों की जानकारी दी।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुरः 'आयुष आहार' थीम के तहत, एनआईए ने त्रिफला जैम और रागी बिस्कुट सहित सात्विक आहार उत्पादों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। सात्विक भोजन के सिद्धांतों पर संवाद आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी): इन्होंने पौष्टिक कुकीज, एनी ब्रेड और जीतायु चाय जैसे आयुर्वेदिक पोषण उत्पादों को प्रदर्शित किया। आरएवी ने आयुर्वेदिक ज्ञान पर आधारित स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट क्विज आयोजित करके छात्रों और अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों को आकर्षित किया।

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई): संस्थान ने वाई-ब्रेक (कार्यकारी व्यक्तियों के लिए त्वरित विश्राम), योग प्रदर्शनों और इंटरैक्टिव क्विज के माध्यम से तनाव कम करने के लिए सरल योग अभ्यासों को प्रदर्शित किया।

यूनानी चिकित्सा: सीसीआरयूएम और एनआईयूएम ने हरेरा, यूनानी कहवा और हलवा घीकवार जैसे पारंपरिक यूनानी खाद्य पदार्थो को प्रदर्शित किया। एक प्रमुख आकर्षण डिजिटल मिजाज-मूल्यांकन कियोस्क था। मुफ्त परामर्श और दवा वितरण भी किया गया।

सिद्ध प्रणाली: एनआईएस और सीसीआरएस ने निवारक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हिबिस्कस इन्फ्यूजन टी और पंचमुट्टी कांजी जैसे सिद्ध-प्रेरित पौष्टिक खाद्य पदार्थो का प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी): एनएमपीबी ने औषधीय पौधों की जीवंत प्रदर्शनी लगाई और हर्बल जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ''अटल आयुष महोत्सव'' के तहत औषधीय पौधे वितरित किए।

अन्य आकर्षण: सीसीआरएच ने होम्यो- पैथी ओपीडी लगाई। राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान ने सोवा-रिग्पा आहार की जानकारी दी। आयुष स्टार्ट-अप्स ने उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए अभिनव कल्याण उत्पादों का प्रदर्शन किया।

एक्टिविटी जोन: बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, स्वास्थ्य-आधारित सांप-सीढ़ी के खेल और मिलेट क्विज जैसी इंटरैक्टिव गतिविधियाँ आयोजित की गई।

यह मंडप पारंपरिक आयुष ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के साथ एकीकृत करने और निवारक, किफायती स्वास्थ्य सेवा पर आयुष मंत्रालय के दृष्टिकोण की पुष्टि करता है।

आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने वर्मम थेरेपी का उपयोग करके उड़ान के दौरान त्वरित चिकित्सीय हस्तक्षेप करने वाले सिद्ध चिकित्सकों की सराहना की

सूत्र/रे.स.ब्यू- आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने हाल ही में एक उड़ान के दौरान सहयात्री को समयोचित चिकित्सीय सहायता प्रदान करने वाले दो सिद्ध चिकित्सकों, डॉ. इलावरासन और डॉ. गौतम, के अनुकरणीय आचरण और नैदानिक कौशल की सराहना की है। श्री कोटेचा ने नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की और वास्तविक जीवन की आपातकालीन स्थिति में उनकी सूझबूझ, जिम्मेदारी की भावना और सिद्ध वर्मम तकनीकों के प्रभावी उपयोग के लिए धन्यवाद दिया।

उड़ान के दौरान, एक यात्री को अचानक चक्कर आने लगे, और चिकित्सा सहायता के लिए घोषणा की गई। सिद्ध चिकित्सकों, डॉ. इलावरासन और डॉ. गौतम, ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए यात्री की जाँच की और शास्त्रीय सिद्ध लिटलेचर में वर्णित विशिष्ट वर्मम उत्यदीपन तकनीकों का प्रयोग किया। कुछ ही मिनटों के भीतर यात्री को काफी राहत मिली और स्थिति स्थिर हो गई।

आयुष मंत्रालय के सचिव ने डॉक्टरों के शांत, पेशेवर और करुणामय हस्तक्षेप की प्रशंसा की। उन्होंने जोर दिया कि ऐसी परिस्थितियों में सिद्ध वर्मम चिकित्सा का व्यावहारिक उपयोग आपात स्थितियों में इसकी सहायक क्षमता को उजागर करता है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा वितरण में उनकी व्यापक उपयोगिता बढ़ाने के लिए सिद्ध वर्मम तकनीकों के बारे में अधिक जन जागरूकता और संरचित प्रशिक्षण के महत्व को भी रेखांकित किया।

आयुर्वेद फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान-संचालित नवाचार को मजबूत करने के लिए सीसीआरएएस ने सिद्धि 2.0 लॉन्च किया

सूत्र/रे.स.ब्यू- आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने विजयवाड़ा में अपनी प्रमुख उद्योग-अनुसंधान इंटरफेस पहल, सिद्धि 2.0 (औषधि विकास, स्वास्थ्य सेवा और एकीकरण में वैज्ञानिक नवाचार) का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई), विजयवाड़ा और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) विजयवाड़ा क्षेत्र ने मिलकर इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रोफेसर वीडी रबीनारायण आचार्य और आंध्र प्रदेश सरकार के निदेशक (आयुष) श्री के. दिनेश कुमार, आईएएस सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। उद्घाटन के दौरान सीसीआरएएस ने अपना औषधीय-ऐतिहासिक प्रकाशन 'भारत में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि विनियमों का विकास' और एक औषधि सूची प्रबंधन प्रणाली पोर्टल भी जारी किया।

'सिद्धि 2.0' पहल अनुसंधान-आधारित उत्पाद विकास, स्वदेशी प्रौद्योगिकी उन्नति और त्वरित अनुवाद मार्ग की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो प्रगति-2024 की गति पर आधारित है। प्रो. आचार्य ने जीवनशैली की बीमारियों के संदर्भ में आयुर्वेद की प्रासंगिकता पर जोर दिया और उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि संयुक्त कार्य से उत्पन्न बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को समान रूप से साझा किया जाएगा।

सीसीआरएएस के उप महानिदेशक डॉ. एन. श्रीकांत ने बताया कि परिषद ने 150 से अधिक आयुर्वेदिक योगों को मान्यता दी है और उद्योग को सीसीआरएएस के व्यापक डेटा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। सीआईआई की अध्यक्ष डॉ. वी. नागलक्ष्मी ने अनुसंधान, शिक्षा और उद्योग के समन्वय के महत्व पर बल दिया।

इस कार्यक्रम में हिमालय वेलनेस कंपनी जैसी अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें दक्षिण भारत की 25 से अधिक प्रमुख आयुर्वेदिक दवा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। 'सिद्धि 2.0' का लक्ष्य सीसीआरएएस प्रौद्योगिकियों को उद्योग द्वारा व्यापक रूप से अपनाना, गुणवत्ता ढांचों को उन्नत करना और विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी आयुर्वेदिक औषधियों के विकास को बढ़ावा देना है।

प्रमाणन आधारित आयुर्वेदिक उत्पाद स्वास्थ्य क्षेत्र का भविष्य हैं: केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, औषधि विकास, स्वास्थ्य सेवा एकीकरण में वैज्ञानिक नवाचार- सिद्धि का द्वितीय चरण आरंभ करेगा, जिससे देश भर में अनुसंधान आधारित आयुर्वेद औषधि नवाचार को बढ़ावा मिलेगा

क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान- विजयवाड़ा में दो दिवसीय संवाद सम्मेलन में चिकित्सा अनुसंधानों के व्यावहारिक समाधानों में इस्तेमाल, औषधि क्षेत्र में साझेदारी तथा केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के नवोन्मेषों के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने पर विमर्श होगा

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), भारतीय उद्योग संघ विजयवाड़ा जोन के साथ मिलकर क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, विजयवाड़ा में 25 और 26 नवंबर, 2025 को उद्योग जगत के साथ अनुसंधान समेकन कार्यक्रम - सिद्धि का द्वितीय चरण आरंभ करेगा।

केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री प्रतापराव जाधव, ने कहा कि यह पहल पारंपरिक औषधि क्षेत्र को बढ़ावा देने और आयुष को एक वैज्ञानिक आधार पर स्थापित स्वास्थ्य प्रणाली में बदलने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने जोर दिया कि अनुसंधान परिणामों को विश्व-स्तरीय उच्च गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक उत्पादों में बदलने के लिए उद्योगों के साथ जुड़ाव आवश्यक है।

आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि 'सिद्धि द्वितीय चरण' सीसीआरएएस की वैज्ञानिक शक्ति और भारत के आयुष उद्योग की उत्पादन क्षमताओं को एकीकृत करने वाली समय पर की गई पहल है, जो विनियामक सुगमता और उत्पादन में तेजी लाएगी।

'सिद्धि द्वितीय चरण' अनुसंधान-आधारित उत्पादन, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल और वैज्ञानिक तथा चिकित्सा अनुसंधान को व्यावहारिक समाधानों में बदलने पर केंद्रित है। यह पिछले वर्ष प्रगति-2024 द्वारा उत्पन्न गतिशीलता पर आधारित है। सीसीआरएएस महानिदेशक प्रो. रविनारायण आचार्य ने बताया कि दो दिवसीय कार्यक्रम में सीसीआरएएस के अनुसंधान परिणामों को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे उत्पादों के विकास, सत्यापन और विस्तारण का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस सम्मेलन में हिमालया, आईएमपीसी-ओपीएस, और लैला न्यूट्रा प्राइवेट लिमिटेड सहित दक्षिण भारत की 25 से अधिक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि कंपनियों के साथ-साथ अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक, और शैक्षणिक विशेषज्ञ भाग लेंगे। राष्ट्रीय अनुवाद त्वरक के रूप में स्थापित, 'सिद्धि द्वितीय चरण' का उद्देश्य सीसीआरएएस प्रौद्योगिकियों को उद्योग द्वारा अपनाए जाने को विस्तारित करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी आयुर्वेदिक औषधियों के विकास को बढ़ावा देना है।

भारतीय रेलवे काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए तमिलनाडु से बनारस तक सात विशेष ट्रेनें चला रहा है।

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेलवे कन्याकुमारी, चेन्नई, कोयंबटूर और बनारस के बीच सात विशेष ट्रेनों की श्रृंखला चला रहा है ताकि काशी तमिल संगमम 4.0 में बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और तमिल भाषी क्षेत्र और काशी के प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जा सके। इन विशेष ट्रेनों को इस बहुदिवसीय सांस्कृतिक विसर्जन कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए निर्बाध यात्रा, आरामदायक लंबी दूरी की कनेक्टिविटी और समय पर आगमन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया है।

इन सेवाओं की शुरुआत 29 नवंबर 2025 को कन्याकुमारी से पहली ट्रेन के प्रस्थान के साथ हुई। इसके बाद चेन्नई से एक अतिरिक्त विशेष ट्रेन रवाना हुई। अगली प्रस्थान 3 दिसंबर को कोयंबटूर से, 6 दिसंबर को चेन्नई से, 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से, 9 दिसंबर को कोयंबटूर से और 12 दिसंबर 2025 को चेन्नई से एक और सेवा निर्धारित है। इन नियोजित प्रस्थानों के साथ, तमिलनाडु के प्रमुख शहरों से बनारस के लिए कुल सात विशेष ट्रेनें एक सुव्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से चलेंगी।

समय पर वापसी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने बनारस से कई विशेष वापसी सेवाओं की व्यवस्था की है। इनमें 5 दिसंबर को कन्याकुमारी, 7 दिसंबर को चेन्नई और 9 दिसंबर को कोयंबटूर के लिए प्रस्थान शामिल हैं, इसके बाद 11 दिसंबर को चेन्नई, 13 दिसंबर को कन्याकुमारी, 15 दिसंबर को कोयंबटूर और 17 दिसंबर 2025 को फिर से चेन्नई के लिए अतिरिक्त वापसी सेवाएँ निर्धारित हैं।

काशी तमिल संगमम 4.0, तमिलनाडु और काशी के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंध को जारी रखता है। यह संस्करण ''आइए तमिल सीखें - तमिल कर्कलम'' विषय पर केंद्रित है, जो वाराणसी के स्कूलों में तमिल सीखने की पहल, काशी क्षेत्र के छात्रों के लिए तमिलनाडु के अध्ययन दौरों और तेनकाशी से काशी तक प्रतीकात्मक ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

काशी तमिल संगमम 4.0 एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार को मूर्त रूप देता है, जो लोगों को अपनी संस्कृति से परे संस्कृतियों की समृद्धि को समझने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित, आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रमुख ज्ञान साझेदार के रूप में कार्य कर रहे हैं, और रेलवे सहित दस मंत्रालयों की भागीदारी, दोनों क्षेत्रों के छात्रों, कारीगरों, विद्वानों, आध्यात्मिक नेताओं, शिक्षकों और सांस्कृतिक व्यवसायियों को एक साथ लाती है, जिससे उनके बीच विचारों, सांस्कृतिक प्रथाओं और पारंपरिक ज्ञान का आदान-प्रदान होता है।

इन सात विशेष ट्रेनों को चलाकर और एक सावधानीपूर्वक नियोजित, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध यात्रा कार्यक्रम का समन्वय करके, भारतीय रेलवे देश के विविध क्षेत्रों को जोड़ने और तमिलनाडु और काशी के बीच साझा विरासत को सुदृढ़ करने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

इरकॉन की गृह पत्रिका 'नवनिर्माण' को राजभाषा सम्मान 2025 से किया गया सम्मानित

सूत्र/रे.स.ब्यू- 22 नवम्बर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के दौरान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। संस्थान की गृह पत्रिका 'नवनिर्माण' को हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 'राजभाषा सम्मान 2025' से नवाजा गया है।

इस गौरवशाली अवसर पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कार्यालय की ओर से उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री राजेश मिश्रा और अनुवादक अधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार दूबे ने यह सम्मान ग्रहण किया। समारोह में उपस्थित इथोपिया के राजदूत, सूरीनाम की राजदूत एवं विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से अधिकारियों को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय मंच पर राजभाषा के प्रति इरकॉन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए पूरे देश के 5,868 रेलवे स्टेशनों पर व्हीलचेयर उपलब्ध हैं

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि रेलवे द्वारा दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों आदि के परिचारकों को रेलगाड़ियों से आने-जाने के लिए निःशुल्क व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि, परिचारक उपलब्ध न होने पर, दिव्यांगजनों आदि को लाने-ले जाने के लिए पूर्व निर्धारित मामूली दर पर लाइसेंस प्राप्त सहायक (पोर्टर) किराए पर लिए जा सकते हैं। इस संबंध में जानकारी रेलवे स्टेशन परिसर में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाती है। वर्तमान में, भारतीय रेलवे के 5868 स्टेशनों पर व्हीलचेयर उपलब्ध हैं।

बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई अन्य पहलों में निम्नलिखित पहल शामिल हैं:

(i) कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को बुकिंग के समय सीट उपलब्ध होने पर, बिना किसी विकल्प के भी, स्वचालित रूप से लोअर बर्थ आवंटित करने का प्रावधान है।

(ii) शयन यान श्रेणी में प्रति कोच छह से सात लोअर बर्थ, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (3एसी) में प्रति कोच चार से पांच लोअर बर्थ और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी (2एसी) में प्रति कोच तीन से चार लोअर बर्थ (रेलगाड़ियों में उस श्रेणी के कोचों की संख्या के आधार पर) का संयुक्त कोटा वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

(iii) सभी क्षेत्रीय रेलवे के उपनगरीय खंडों पर चलने वाली लोकल रेलगाड़ियों के पूरे समय के दौरान प्रथम और अंतिम द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कम से कम 7 सीटें आरक्षित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

(iv) रेलगाड़ियों के प्रस्थान के बाद, यदि रेलगाड़ियों में निचली बर्थ खाली हों और विकलांग रियायत के तहत बुकिंग कराने वाला कोई दिव्यांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक या गर्भवती महिला, जिसे ऊपरी/मध्य बर्थ आवंटित की गई हो, खाली निचली बर्थ के आवंटन के लिए संपर्क करे, तो रेलगाड़ियों में मौजूद टिकट चेकिंग स्टाफ को चार्ट में आवश्यक प्रविष्टियाँ करते हुए उन्हें खाली निचली बर्थ आवंटित करने का अधिकार दिया गया है।

(v) दिव्यांगजनों के लिए रियायती सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद, राजधानी/शताब्दी प्रकार की रेलगाड़ियों सहित सभी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में निम्नलिखित आरक्षण कोटा आरक्षित किया गया है:-

d) स्लीपर श्रेणी में चार बर्थ (दो लोअर और दो मिडिल)। ख) 3ई या 3ए श्रेणी में चार बर्थ (दो लोअर और दो मिडिल)। (इन दोनों श्रेणियों में से, यानी 3ई/3ए में, किस श्रेणी के लिए कोटा आरक्षित किया जाना है, यह संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा रेलगाड़ियों में उस श्रेणी के उपलब्ध कोचों की संख्या को ध्यान में रखते हुए तय किया जा सकता है)। ग) गरीब रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के विशेष रूप से विकलांगों के लिए आरक्षित (एसएलआरडी) कोच में चार बर्थ। घ) उन रेलगाड़ियों में आरक्षित द्वितीय सीटिंग (2एस)/ वातानुकूलित चेयर कार (सीसी) में चार सीटें जिनमें इन श्रेणियों के दो से अधिक कोच हैं।

(छ) निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों (पूरी तरह से आरक्षित रेलगाड़ियों को छोड़कर) में, एसएलआरडी कोचों को दिव्यांगजनों के विशेष उपयोग के लिए आरक्षित अनारक्षित कोचों के रूप में माना जाना चाहिए।

दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, रोगी यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए 79 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 196 बैटरी से चलने वाले वाहन उपलब्ध हैं

(vii) गरीब रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और अन्य पूर्णतः आरक्षित रेलगाड़ियों के मामले में, ये कोच दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित माने जाएंगे, जो विकलांग रियायत पर यात्रा कर रहे हैं और उन्हें उस श्रेणी का किराया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर देना होगा।

(viii) यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली के माध्यम से जारी टिकटों में, जहां तक संभव हो, एक निचली बर्थ दिव्यांगजनों को आवंटित की जाए और उनके साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति को, सीट की उपलब्धता के अधीन, दिव्यांगजन के पास मध्य/ऊपरी बर्थ आवंटित की जाए।

(ix) रेलगाड़ियों के प्रस्थान के बाद, यदि रेलगाड़ियों में खाली लोअर बर्थ उपलब्ध हैं और यदि दिव्यांग रियायती टिकट पर बुकिंग कराने वाले किसी दिव्यांगजन को ऊपरी/मध्य बर्थ आवंटित की गई है और वह खाली लोअर बर्थ के आवंटन के लिए आता है, तो रेलगाड़ियों में मौजूद टिकट चेकिंग स्टाफ को चार्ट में आवश्यक प्रविष्टियाँ करते हुए उन्हें खाली लोअर बर्थ आवंटित करने का अधिकार दिया गया है।

(x) विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों पर दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व सांसदों, विधायकों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आरक्षण अनुरोधों के निपटान के लिए अलग-अलग काउंटर निर्धारित किए गए हैं, यदि प्रति शिफ्ट औसत मांग 120 टिकटों से कम न हो। यदि दिव्यांगजनों सहित इनमें से किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए एक अलग काउंटर निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है, तो कुल मांग के आधार पर एक या दो काउंटर इन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के आरक्षण अनुरोधों के निपटान के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

(xi) क्षेत्रीय रेलवे द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र के आधार पर दिव्यांगजनों और कुछ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को रियायती ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान की गई है। दिव्यांगजनों और कुछ बीमारियों से पीड़ित रोगियों के साथ आने वाला एक सहायक भी इस रियायत का पात्र है।

(xii) प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर बैटरी से चलने वाले वाहन (बीओवी) उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह सुविधा कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व/प्रायोजन के माध्यम से निःशुल्क और सेवा प्रदाता के माध्यम से शुल्क के आधार पर प्रदान की जाती है। वर्तमान में, 79 स्टेशनों पर 196 बीओवी उपलब्ध हैं, जिनमें से 165 शुल्क के आधार पर, 10 प्रचार के माध्यम से निःशुल्क और 21 सीएसआर के माध्यम से निःशुल्क हैं।

माघ मेले की तैयारियों के मद्देनजर रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, रामबाग एवं झूंसी स्टेशनों का संयुक्त निरीक्षण

सूत्र/रे.स.ब्यू- माघ मेला 2025 की व्यापक तैयारियों को देखते हुए रेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, प्रयागराज रामबाग तथा झूंसी स्टेशनों का संयुक्त निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त प्रयागराज श्रीमती सौम्या अग्रवाल, मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज मंडल श्री रजनीश अग्रवाल, जिला अधिकारी प्रयागराज श्री मनीष कुमार वर्मा, अपर पुलिस आयुक्त श्री अजय पाल शर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक (सामान्य) श्री दीपक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान मेला अवधि में श्रद्धालुओं के सुचारु आवागमन हेतु समग्र व्यवस्था और विस्तृत कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था तथा प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में मार्गदर्शन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख स्थानों पर 'दिशा-निर्देश साइनेज' को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

इसके साथ ही माघ मेले के दौरान लखनऊ, अयोध्या एवं वाराणसी दिशाओं में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को प्रयाग एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशनों की ओर उचित रूप से मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रचार प्रसार, सूचना प्रसारण तथा उपयुक्त स्थानों पर साइनेज स्थापित करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

अधिकारियों ने प्रयागराज जंक्शन,प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज रामबाग एवं झूंसी स्टेशनों पर यात्री आश्रयों, कंट्रोल टावर, प्रवेश एवं निकास मार्गो सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर उनकी कार्यप्रणाली का आकलन किया तथा उन्हें और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

रेल प्रशासन एवं सिविल प्रशासन बेहतर समन्वय से माघ मेला अवधि में यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

महाप्रबंधक/उत्तर मध्य रेलवे ने किया झूंसी, प्रयागराज रामबाग एवं प्रयाग जंक्शन स्टेशनों का निरीक्षण

सूत्र/रे.स.ब्यू- माघ मेला -2026 की व्यापक तैयारियों को देखते हुए महाप्रबंधक/उत्तर मध्य रेलवे, श्री नरेश पाल सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ झूंसी, प्रयागराज रामबाग एवं प्रयाग जंक्शन स्टेशनों स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, श्री एस एस चंद्रयानय प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, श्री ब्रिजेन्द्र कुमारय प्रयागराज मण्डल के अपर मंडल रेल प्रबंधक/इंफ्रा, श्री नवीन प्रकाशय अपर मंडल रेल प्रबंधक/सामान्य/श्री दीपक कुमार एवं लखनऊ मण्डल व वाराणसी मण्डल के अधिकारी उपस्थित रहे ।

निरीक्षण के दौरान माघ मेला -2026 अवधि में श्रद्धालुओं के सुचारु आवागमन हेतु तैयारियों और विस्त त कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था तथा प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में मार्गदर्शन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख स्थानों पर 'दिशा-निर्देश साइनेज' को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया । इसके साथ ही माघ मेले के दौरान लखनऊ, अयोध्या एवं वाराणसी दिशाओं में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रचार प्रसार, सूचना प्रसारण तथा उपयुक्त स्थानों पर साइनेज स्थापित करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई । महाप्रबंधक/उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयाग जंक्शन पर निरीक्षण के दौरान प्रयाग जंक्शन के पावर केबिन एवं इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक/उत्तर मध्य रेलवे ने पावर केबिन एवं इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर कार्यप्रणाली को बिंदुबार देखा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर से रेल प्रशासन और मेला प्रशासन के बीच समन्वय किया जाता है । इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर में संगम क्षेत्र एवं शहर के स्टेशनों से सीधा प्रसारण निरंतर मिलता है । यहाँ से यात्री आश्रय, प्लेटफॉर्म एवं फुट ओवर ब्रिज की भीड़ पर नजर रखी जाती है एवं यात्री उद्घोषणा प्रणाली से आवश्यक सूचना और निर्देश जारी किए जाते है ।

जिलाधिकारी ने माघ मेला क्षेत्र का भ्रमण करते हुए तैयारियों का लिया जायजा, शेष बचे हुए कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने के दिए निर्देश

सूत्र/रे.स.ब्यू-जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने माघ मेलाधिकारी श्री ऋषिराज के साथ मेला क्षेत्र का भ्रमण करते हुए मेले की बसावट हेतु की जा रही तैयारियों का जायजा लिया तथा सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने आचार्य बाड़ा, दण्डीबाड़ा, खाकचौक सहित अन्य क्षेत्रों एवं ओल्ड जीटी मार्ग का निरीक्षण किया और वहां पर चल रहे समतलीकरण, सड़क बनाने हेतु चकर्ड प्लेट बिछाने, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति व सीवर लाइन बिछाने का कार्य, विद्युत विभाग की एचटी व एलटी लाइन खींचने का कार्य एवं घाटो के निर्माण एवं उनके कटाव निरोधक कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यो की भौतिक प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने पीडब्लूडी, विद्युत, जल निगम, स्वास्थ्य विभाग के सम्बंधित अधिकारियों को मैनप वर, शिफ्ट व आवश्यक संसाधन बढ़ाकर कार्य की प्रगति में तेजी लाये जाने एवं सभी व्यवस्थायें शीघ्रता से सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए है। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने नागवासुकी मंदिर के सामने नाले के पानी की जिओट्यूब के माध्यम से शोधन हेतु की जा रही व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कार्यो को शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने निर्देश दिए है। इस अवसर पर डीसीपी ट्रैफिक श्री नीरज कुमार पाण्डेय, अपर मेलाधिकारी श्री दयानंद प्रसाद, उपजिलाधिकारी श्री विवेक शुक्ला, श्री अभिनव पाठक, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी श्री सुरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता जल निगम श्री आशुतोष सहित अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

माघ मेला 2026 को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के दृष्टिगत मेला सलाहकार समिति की बैठक

सूत्र/रे.स.ब्यू- माघ मेला 2026 को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के दृष्टिगत मेला सलाहकार समिति की बैठक मेला प्राधिकरण कार्यालय स्थित आईसीसीसी सभागार में संपन्न हुई जिसमें पूज्य संत-महात्माओं, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए। सर्वप्रथम अपर मेला अधिकारी, माघमेला श्री दयानंद प्रसाद एवं पुलिस अधीक्षक माघमेला श्री नीरज कुमार पांडेय ने प्रशासन एवं पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाओं की पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। तत्पश्चात सभी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधियों ने एक एक कर अपनी बात रखी। इस क्रम में सर्वप्रथम तीर्थ पुरोहितों का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री रामबाबू ने श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, सभी सेक्टरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहे तथा माघ मेले में मोबाइल कनेक्टिविटी भी सुचारू ढंग से चलती रहे यह सुनिश्चित करने की अपील की। नाविक संघ के प्रतिनिधि पप्पू लाल ने जानकारी देते हुए कहा की कुंभ की भीड़ को देखते हुए यहाँ के नाविकों ने माघ मेले के दृष्टिगत काफी भारी तादाद में नावों की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। अतः बाहर की नावों का रजिस्ट्रेशन करने एवं मोटर बोट चलाने से रोका जाना चाहिए। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन श्री अन्नू गुप्ता ने पुलिस बूथ पर तैनात पुलिसकर्मियों को अच्छे से प्रशिक्षण देने के पश्चात ही उनकी तैनाती करने का सुझाव दिया जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं की अधिक से अधिक मदद की जा सके। आचार्य बाड़ा के उपस्थित प्रतिनिधि ने अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जहाँ उनकी बसावट की जा रही है वहाँ अभी तक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य सुविधाएं जैसे शौचालयों की संख्या को बढ़ाने की भी अपील की। इसका समर्थन करते हुए श्री कौशलेन्द्र प्रपचार्यजी महाराज ने आचार्य बाड़ा एवं अन्य संस्थाओं की मूलभूत सुविधाएँ बढ़ाने की अपील। खाक चौक के उपस्थित प्रतिनिधि ने प्रशासन से भूमि आवंटन के समय भूमि के साइज के अनुसार एक नया मानक बनाते हुए कितने बड़े प्लॉट में कितने शौचालयों की आवश्यकता है इसका आकलन कर भविष्य में सुविधाएं देने का सुझाव दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय के साथ साधु संन्यासियों की संख्या बढ़ रही है अतः संस्थाओं को अधिक भूमि एवं मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। श्री लेटे हनुमान जी के महंत श्री बलबीर गिरिजी महाराज ने मेला क्षेत्र में एक बेहतर साइनेज व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। सांसद श्री उज्ज्वल रमन सिंह के प्रतिनिधि ने सभी पीपा पुलों को श्रद्धालुओं हेतु खोले रखने एवं उसमें सुचारू ढंग से ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। शहर उत्तरी विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी ने फाफामऊ से शहर आने हेतु बनाए जा रहे दो अतिरिक्त पॉन्टून पुलों को समय के अंतर्गत बनाने, श्रद्धालुओं को किसी भी हाल में घाटों के निकट सोने न देने तथा नागवासुकी के सामने बनाई गई कोस्टल रोड पर स्थायी रूप से बिजली की व्यवस्था करने के सुझाव दिए। महापौर श्री उमेश चंद्रगणेश केसरवानी ने सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की उचित व्यवस्था करने तथा अधिक भीड़ की संभावना के दृष्टिगत पहले से ही शहर के कुछ स्कूलों में होल्डिंग एरिया की व्यवस्था रखने का सुझाव दिया। अंत में अपर मेला अधिकारी श्री दयानंद प्रसाद ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी से माघ मेला के आयोजन को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिए सहयोग प्रदान करने की अपील की।

Kalaburagi–Bengaluru Vande Bharat to Operate with Revised Morning Schedule

Source/RSB - The departure timing of the Kalaburagi–Bengaluru Vande Bharat Express has been rescheduled, with the revised timetable set to take effect from January 1, 2026. As per the updated schedule, the train will now depart at 6:10 am instead of the earlier 5:10 am. Railway officials said the change has been made to make travel more convenient for a wide range of passengers, including students, senior citizens, women, and business travellers. The revised timing is expected to ease early-morning travel pressures and improve overall passenger comfort.

In a related announcement, Central Railway also stated that direct transportation of silk cocoons to Ramanagara will be facilitated. Additionally, the railways have indicated that OTP-based verification for Tatkal ticket bookings will soon be made mandatory, a move aimed at strengthening the ticketing process.

The announcements reflect a combination of passenger-focused timetable adjustments and operational updates within the railway system.

Central Railway's Mumbai Division enhances passenger amenities at stations

Source/CR- Central Railway continues its commitment to provide better passenger convenience and safety by enhancing station amenities across its network. Significant upgrades and installations have been carried out to ensure a comfortable, accessible, and seamless travel experience for all commuters.

Key highlights of amenities provided by Mumbai division in the month of October- 2025 are as under:

PASSENGER COMFORT

Escalators:

- 4 escalators have been provided which includes 2 escalators each at Dombivili (platform no 3 & 4) and Kurla (platform no 5 & 6) stations.

BLDC Fans & Air circulator fans:

- 92 additional Brushless Direct Current (BLDC) fans have been provided at various stations. BLDC fans are fans that use a brushless DC motor which is more energy efficient and makes less noise than the conventional induction motor fans. They use electronic controllers and permanent magnets instead of the carbon brushes, which significantly reduces energy consumption by 50 to 70%.
- 33 new additional Air circulator fans have been provided at various stations. These air circulators create a continuous & consistent air circulation unlike the conventional fans that blow air in one direction only.

New Energy efficient LED tube lights:

- 386 LED tube lights have been provided at various stations. These LED tube lights are energy efficient with longer lifespan and reduced maintenance and replacement costs. They provide better illumination and are environment friendly.

PASSENGER INFORMATION

GPS clocks & Public address system

- One GPS tower clock has been installed at Uran station.
- Public Address System at Matunga station has been upgraded to IP based system with 35 speakers for clear & better reach of information.

PASSENGER TICKETING

Mobile UTS Sahayaks

- Facility of Mobile UTS Sahayaks has been introduced on Central Railway with 3 Sahayaks operating at CSMT. Provided with a mobile phone and a small ticket printing machine strapped on themselves, these M-UTS Sahayaks go from person to person waiting on the concourse or in the holding areas or on railway premises and issue tickets on payment of the ticket fare.

Central Railway remains steadfast in its efforts to upgrade station facilities, incorporating modern technology and infrastructure improvements to enhance the overall travel experience. These initiatives are aligned with the vision of a passenger-friendly railway network, emphasizing accessibility, convenience, and safety.

Indian Railways Partners with ROQIT to Roll Out AI-Based Parcel Logistics System

Source/RSB- In a move to modernise its parcel delivery operations, Indian Railways has entered into a partnership with ROQIT to build and deploy an artificial intelligence-enabled logistics platform focused on small and medium-weight consignments. Under the agreement, ROQIT will be responsible for developing and implementing an AI-driven solution designed to improve operational efficiency, real-time tracking, and overall customer engagement within railway parcel services. The initial pilot of the platform is planned to be launched in collaboration with South Central Railway in early 2026. Following the pilot phase, the system is expected to be scaled up across the country, supporting a fully digital, environmentally sustainable, and customer-oriented parcel delivery model. The initiative reflects Indian Railways' broader push to adopt advanced technologies to enhance logistics performance and strengthen last-mile delivery capabilities nationwide.

132-Crore Wagon Supply Order Awarded to Texmaco Rail

Texmaco Rail & Engineering Ltd.

Source/RSB-Texmaco Rail & Engineering has secured a railway wagon manufacturing contract valued at ₹132 crore from Touax Texmaco Railcar Leasing, a joint venture associated with the company. The order covers the supply of BLSS and BVCM category wagons and will be executed in multiple phases. As per the contract terms, the entire delivery schedule is expected to be completed by July 2026. Company sources indicated that the wagons will be manufactured in line with the prescribed quality, safety, and performance standards. The phased execution approach is intended to ensure adherence to technical specifications while meeting delivery timelines.

WESTERN RAILWAY ACHIEVES BEST EVER TICKET CHECKING PERFORMANCE

Source/WR- Western Railway has achieved its best ever ticket checking performance during the period from April to October 2025, generating ₹121.67 crore through the detection of about 19 lakh ticketless and irregular passengers, including unbooked luggage cases. This is an increase of 51% over last year, which was ₹80.56 crore and a 14% rise over the Railway Board's target.

According to a press release issued by Chief Public Relations Officer of Western Railway, the WR zone has recorded its second best ever monthly performance in October 2025 with earnings of more than ₹24 crore, their previous best record was of about ₹26 crore in May 2022.

It is noteworthy that Ahmedabad Division registered its best ever ticket checking, with recovery of more than ₹4 crore with 50 thousand cases in October 2025. The Headquarter's Flying Squad also achieved its best ever monthly performance of ₹2.20 crore in October 2025, surpassing the previous best of ₹2 crore in May 2022. Western Railway also recorded multiple record breaking daily earnings during the month of October 2025. WR has achieved almost ₹1.40 crore on 17th October 2025, while Ahmedabad Division achieved more than ₹38 lakh on 18th October 2025, with Ratlam Division achieving almost ₹16 lakh on the same day. The Headquarter's Flying Squad, achieved about ₹16.30 lakh on 19th October 2025.

Air-Conditioned Waiting Hall Inaugurated at Ahmedabad Station, Enhancing Passenger Comfort

Source/RSB- The Ahmedabad railway station unveiled its newly developed Air-Conditioned Waiting Hall on Platform No. 1, marking a significant upgrade in passenger amenities for the region. The facility was inaugurated by Hon'ble MP, Ahmedabad West, Shri Dinesh Makwana and Hon'ble MLA, Dariapur, Shri Kaushik Jain.

Described as the first-of-its-kind facility in the Ahmedabad Division, the waiting hall is designed to provide a more convenient, comfortable, and modern travel experience for passengers.

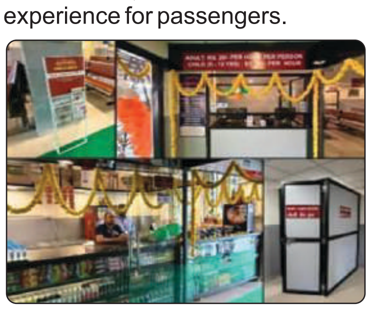

Key Features of the New AC Waiting Hall

- Seating capacity for 250 reserved passengers, ensuring a spacious and relaxed environment
- A dedicated Baby Care Room, offering convenience for traveling families
- Refreshment and beverage counter for quick bites and drinks
- Clean washrooms and bathing facilities for enhanced hygiene
- Multiple mobile charging points to keep devices powered throughout the journey
- Access to reading material and essential items, adding to the overall comfort

The newly inaugurated waiting hall reflects Indian Railways' ongoing commitment to improving passenger-centric services and upgrading station infrastructure across the network.

Indian Railways Deploys First Made-in-India Locomotive Fitted with Kavach Safety Technology

Source/RSB-Indian Railways has rolled out its first indigenously manufactured locomotive equipped with the Kavach automatic train protection system, marking a key milestone in rail safety modernisation. The locomotive was dispatched from the Ajni Loco Shed in Nagpur. The Kavach system, which carries SIL-4 safety certification, is designed to enhance operational safety by automatically preventing over speeding, signal overshooting, and potential train collisions. It functions through continuous real-time data exchange and automated braking interventions when risk conditions are detected. Following the successful completion of trials, Indian Railways has outlined an ambitious expansion plan to install the Kavach safety system across 10,000 locomotives in the coming years, reinforcing its commitment to strengthening rail safety through indigenous technology.

Delhi Metro Signs MoU with IIT Hyderabad's TiHAN for Next-Gen Autonomous Navigation Solutions

Source/DMRC - DMRC has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with IIT Hyderabad's Technology Innovation Hub for Autonomous Navigation (TiHAN). This MoU will leverage each others strength & knowhow in implementation of Autonomous Navigation which is a Safe Smart and Next Gen Mobility solution for last mile connectivity in major metros and public transit in Tier II & III cities. TiHAN is a hub set up by Department of Science & Technology (DST) National Mission in the Cyber Physical Systems for development of Autonomous Navigation and Data Acquisition Systems that enables Ground vehicles, Robots, Unmanned Aerial Vehicles / Drones or other autonomous platforms to navigate and collect data without human interventions.

The MOU was signed by Sh. Shobhan Chaudhuri Advisor / R&D from DMRC and Dr. Santosh Reddy Hub Executive Officer, TiHAN from IIT/Hyderabad in the presence of Dr. Vikas Kumar, MD/DMRCL along with Shri. Manuj Singhal Director / Infrastructure and other Directors from DMRC side and Prof. Malla Reddy, Dean/Innovation and Prof. P. Rajalakshmi from IIT/Hyderabad.

RITES & Botswana Government sign MoU to Modernise Railway and Transport Infrastructure in Botswana.

Source/RSB - RITES Ltd., a prime transport infrastructure consultancy, today signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of the Republic of Botswana, represented by its Ministry of Transport and Infrastructure, to collaborate on the development and modernisation of transport infrastructure in Botswana. The partnership aims to accelerate the growth of Botswana's railway and transport infrastructure by deploying advanced technologies, global best practices, and capacity-building initiatives to strengthen local capabilities and enhance efficiency, safety, and reliability across the sector.

Under the MoU, Botswana will draw upon RITES Limited's extensive technical expertise for the development and modernisation of railway systems. RITES' scope of support will include the supply of rolling stock; commissioning, repair, operation and maintenance support for railway systems; and modernisation of workshops. The collaboration will also cover transport infrastructure development projects spanning railways, highways, bridges, airports, and buildings. In addition, RITES will provide capacity-building and technical training programmes, facilitate knowledge exchange, deliver quality assurance services including third-party inspections, pre-shipment inspections, and final acceptance testing and deploy advanced information technology solutions such as integrated train operations & passenger management systems.

IRCTC Opens Emergency Railway Ticket Facility at Ahmedabad Airport

Source/RSB - To assist air travellers facing travel disruptions, the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), in coordination with the Ministry of Railways, has set up a special emergency railway ticket counter inside the terminal of Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. The newly established helpdesk is aimed at providing immediate assistance to passengers stranded at the airport. With this facility in place, travellers no longer need to leave the terminal to locate a railway station or depend on online booking platforms during emergencies.

Passengers can now directly approach the counter within the airport premises to check train availability and purchase railway tickets on the spot. The initiative is intended to make last-minute travel arrangements more convenient and reduce stress for those affected by unexpected delays or cancellations. The move reflects ongoing efforts to improve passenger support by integrating rail services with major transport hubs such as airports.

Ahmedabad to Host India's First 16-Storey Integrated Railway Station

Source/RSB - Ahmedabad is set to witness a major transformation in rail infrastructure with the development of the country's first railway station rising across 16 floors. Designed as a vertical, multimodal transport hub, the upcoming station will integrate conventional rail services along with the Mumbai–Ahmedabad bullet train, metro connectivity, and road transport facilities. The station is being constructed above the existing platforms at Kalupur Railway Station. The project envisions modern concourses, commercial retail spaces, and seamless passenger transfers between different modes of transport, all within a single structure. Scheduled for completion by July 2027, the new station complex aims to improve passenger movement and ease congestion in one of the city's busiest transit areas. The vertical design is expected to optimise space while enhancing connectivity and travel convenience for commuters. The project marks a significant step toward modernising railway infrastructure and reimagining station design in urban India.

CONCOR Achieves Major Milestone with First-Ever Overseas Reefer Movement and Bill of Lading Issuance

Source/RSB - Shri Sanjay Swarup, CMD, Container Corporation of India Ltd (CONCOR), has launched the first Bill of Lading (BL) issued by CONCOR for export cargo carried in CONCOR's own container, which has sailed to the South East Asia region. This development marks a historic moment for CONCOR as it records its first-ever overseas reefer movement in its own container, the first Bill of Lading issued by the organisation, and the first cargo movement by CONCOR to a South East Asian port. The milestone has been enabled through CONCOR's unified digital system, facilitating effortless online BL creation along with end-to-end cargo visibility. Through this initiative, CONCOR continues to advance the forward integration of its core competencies, with a focus on providing customers seamless access to services anytime and anywhere.

MIC Electronics Approves Capital Raising Plan, Wins Railway Systems Contract

Source/RSB - MIC Electronics has approved a major fund-raising proposal while also securing a key railway-related project. The company's board has cleared plans to raise ₹250 crore through a Qualified Institutional Placement (QIP) and an additional USD 15 million via Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs), with both fund-raising exercises to be carried out in tranches. Alongside the capital-raising approval, the company has received a Letter of Acceptance (LoA) from the Vijayawada Railway Division for the implementation of an IP-based Integrated Passenger Information System. The project is valued at ₹1,49,88, 884.77 and will be executed at ANV and YLM stations. As per the agreement, the passenger information system is scheduled to be completed within 12 months from the date of signing. The project marks another addition to MIC Electronics' portfolio of railway-related technology solutions. Founded in 1988, MIC Electronics is known as a leading manufacturer of LED display systems, with a presence across multiple infrastructure and information display segments.

Bhopal's Private Railway Station Emerges as a Model for Modern Rail Infrastructure

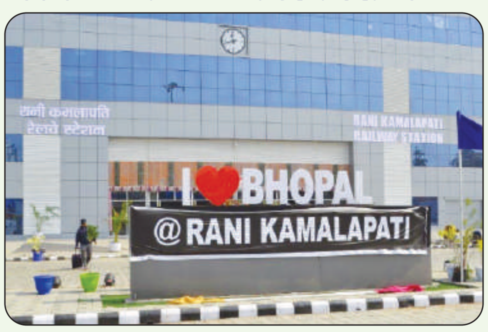

Source/RSB - India's first privately operated railway station at Bhopal has set new standards in cleanliness and passenger convenience. The Rani Kamalapati Railway Station is being widely recognised for its modern design and high levels of hygiene, positioning it as a benchmark for railway redevelop-ment in the country. The station has been redeveloped under a public-private partnership model by Bansal Group at a cost of ₹450 crore. Designed to offer an airport-like experience, the facility features a fully air-conditioned concourse, well-maintained platforms, and upgraded ticketing systems to enhance passenger ease and efficiency. In addition to modern infrastructure, the station provides accessible facilities to ensure barrier-free movement for passengers. The redevelopment also integrates the use of solar energy and focuses on improving overall passenger comfort through thoughtfully planned amenities. With its emphasis on hygiene, sustainability, and user-friendly design, the station stands out as a significant step forward in transforming railway travel experiences in India.

Railways Step In With Capacity Boost Amid IndiGo Flight Disruptions

Source/RSB - Indian Railways has implemented a series of measures to support passengers affected by widespread flight cancellations during the IndiGo crisis. In response to the surge in travel demand, the railways have enhanced capacity across multiple routes. As part of the measures, 37 trains have been augmented with a total of 116 additional coaches. These augmentations have been deployed across 114 enhanced trips to accommodate the increased passenger load. Among the railway zones, Southern Railway has undertaken the highest number of such augmentations, strengthening capacity in 18 trains. In addition to increasing coach strength, Indian Railways also operated four special train services to further assist stranded and affected passengers. These steps have been taken to ensure continuity of travel and minimise inconvenience during the period of disruption in air services. The intervention highlights the railways' role as a dependable alternative transport option during large-scale disruptions in other modes of travel.

Indian Railways to Offer Paid Bedroll Facility for Sleeper Class Travellers

Source/RSB -Indian Railways is preparing to roll out an optional bedding service for passengers travelling in non-AC sleeper coaches, allowing them to access pillows and bedsheets on a paid, request-based basis. The move is aimed at improving comfort without making the facility mandatory for all sleeper-class travellers. As per official information, the new service will be introduced initially on select trains operated by the Southern Railway's Chennai division, with implementation scheduled to begin from 1st January 2026. Passengers who choose to opt in will be able to request a bedroll during their journey by paying a nominal fee. Under the scheme, a charge of ₹50 will apply for a bedding set comprising one bedsheet, one pillow, and a pillow cover. Railway officials said the on-demand model ensures flexibility, enabling passengers to avail themselves of the service only when required, while also enhancing the overall travel experience for sleeper-class